MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up further discussion on the Resolution by Shri Bibhuti Mishra. Four hours in toto were allotted; we have taken two hours, fifteen minutes and now one hour, forty five minutes are left.

Shri Narsingh Narain Pandey may continue his speech.

**श्री नरसिंह नारायण पांडे** (गोरखपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि प्रधान मंत्री जी ने जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम इस देश के सामने रखा है यह कार्यक्रम एक ऐसे समय में रखा गया जिस समय देश के अंदर और देश के बाहर पंजीपरस्त ताकतों और प्रतिक्रियावादी ताकतों का एक गठजोड़ हो रहा था और उस से देश की राजनीति के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। देश के अंदर मिलिट्री को भड़काने की और पुलिस को भड़काने की तथा उत्पादन के स्रोतों को कमजोर करने की कोशिश उन शक्तियों द्वारा एक साजिश के अंतर्गत की जा रही थी। ऐसे समय में जिस समय कि हमारे देश में सूखा पड़ा, हमारे देश में करोड़ शरणार्थी बंगला देश से आए हम को लड़ाई का सामना करना पड़ा, ऐसे समय में जब कि हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर बोझ पड़ रहा था, कुछ शक्तियां इस तरह की साजिश कर रही थीं कि यहां पर राजनैतिक स्थिति और अस्तव्यस्तता इस तरह से कायम की जाय कि इस देश की जो आर्थिक स्वतंत्रता है तथा जिन मूल्यों के तहत हम ने इस देश को आजाद किया, जो हम ने कहा था कि हम करोड़ों आदमियों को जो गांवों में रहते हैं, या जो ऐसी जगहों में रहते हैं जिन के हाथ काम के लिए तड़प रहे हैं, उन का काम देंगे और हर ऐसे आदमी की आंखों से जो किसी तरह की विपदा में आज फंसे हुए हैं, उन के आंसू पोंछेंगे, ऐसे समय में जब हम उन के लिए जद्दोजहद पैदा कर रहे थे तो ये शक्तियां देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही थीं। ऐसे समय में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो एलान किया और जो आपातकालीन स्थिति की घोषणा भारतीय संविधान के तहत की, उस घोषणा के बाद देश में जो एक असाधारण स्थिति चल रही थी, उस पर काबू पाने की कोशिश की और ऐसे समय में यह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का प्रारूप उन्होंने देश के सामने रखा। यह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो है इस से देश में समाजवाद की कोई ऐसी शक्तियां मजबूत नहीं होंगी जिस को कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जो उन गरीबों के दिल और दिमाग में परेशानी है जिस से वह राहत की उम्मीद करते थे वह राहत की सांस वे लेंगे अगर इस कार्यक्रम का सही तरीके से पालन किया जाय।

मैं सब कार्यक्रमों के ऊपर तो विस्तार के साथ नहीं बोल पाऊंगा लेकिन पहला कार्यक्रम जो उत्पादन का और उस के वितरण का है उस के संबंध में मैं आप के समक्ष कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने जो पहला कार्यक्रम रखा देश के सामने उस में कहा था कि जो अत्यावश्यक चीजें हैं जो समाज को सस्ते दामों पर सुलभ होनी चाहिए, वह उत्पादन की व्यवस्था को बढ़ा कर और वितरण की व्यवस्था को मजबूत बना कर सुलभ की जानी चाहिए जिसमें हर आदमी को जिस को जरूरत है वे चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें।

इस सम्बन्ध में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस देश के किसान जोकि अन्न का उत्पादन करते हैं इस देश की सरकार और माननीय प्रधान मंत्री के साथ जोकि सही तरीके से लोगों को आज सूखे नहीं देखना चाहती है लोगों को काम देना चाहती हैं, लोगों को सस्ते भाव पर गल्ला और दूसरी आवश्यक वस्तुयें मुहैया करना चाहती है, मजबूती से उत्पादन के कार्य में लगे। किसानों ने कपास का उत्पादन किया। आपने देखा जब कपास का उत्पादन हुआ तो किसान परेशान हुए और देश के सामने एक

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई कि कपास की खपत किस तरह से की जाये। सभी सदस्यों ने इस सदन में इस बारे में चर्चा की कि कपास के मूल्य ठीक ढंग से निर्धारित किये जायें लेकिन क्या हुआ ? आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे माननीय सदस्य, श्री सी० डी० देसाई जोकि इस समय यहां पर मौजूद नहीं है, उन्होंने कहा था कि कपास के भाव इतने गिरते जा रहे हैं कि जो लागत मूल्य है उसके नीचे भी भाव जा रहे है। उसी प्रकार से जहां तक अन्य गेहूं की पैदावार का सम्बन्ध है, सूखे और अन्य तमाम परेशानियों के बावजूद हमने तहैया किया कि अपने देश में गल्ला पैदा कर उसका भण्डार बना करके वितरण व्यवस्था को मजबूत करेंगे, सस्ते भाव पर लोगों को गल्ला देंगे और हमने उसका भाव भी निश्चित करने की कोशिश की। हमने राशन की सस्ती दूकानों के द्वारा सुदूर अंचलों में गल्ला पहुंचाने की कोशिश की। हमने अपनी गल्ले की उपज बढ़ाई हमारे यहां 114 लाख टन गल्ला हुआ। अभी कुछ दिन पहले माननीय कृषि मन्त्री जी ने मद्रास में कहा कि हमारे यहां 5–6 परसेंट गल्ले की कमी है। यदि हम लोग अपनी आदतों को कन्ट्रोल करें और हमारे यहां जो गल्ला वेस्ट होता है उसका सचय करें तो इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम 60–70 लाख टन अनाज का भण्डार बनायेंगे। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल होता है उसका जहां तक हो सके कम करें ताकि अपने देश का फारेन एक्सचेंज दूसरे देशों को न देना पड़े। उन्होंने यह तमाम बातें कहीं लेकिन आप जानते है अनाज पैदा होने के बाद गेहूं की सपोर्ट प्राइस का क्या हाल हुआ, गेहूं के दाम कितने गिर रहे है ? सरकार ने गेहूं और धान के लिए सपोर्ट प्राइस निश्चित की है लेकिन अगर उसका भाव इतना नीचे जाने लगे तो आप जानते हैं किसानों की क्या स्थिति होगी। वही स्थिति आज सारे देश में किसानों की हो रही है इसी प्रकार पिछले साल हमारे देश में चीनी का उत्पादन ज्यादा हुआ देश में और हमारे प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को थोड़ी सी राहत दी गई, उनके गन्ने का भाव साढ़े चौदह रुपए कर दिया गया फी क्वींटल जिसका परिणाम हुआ कि 48–49 लाख टन चीनी की पैदावार हुई। उसी के मुताबिक गुड़ और खण्डसारी की पैदावार भी हुई। इसके फलस्वरूप हमारे देश को चार सौ करोड़ की फोरन एक्सचेंज प्राप्त हुआ। हम विदेशों को एक मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने दुनिया के चीनी बाजार में घुस करके फोरेन एक्सचेंज कमाया लेकिन किसानों की स्थिति क्या है ? आज भी किसान जो गेहूं पैदा करते है चावल पैदा करते है चीनी पैदा करते है जूट और कपास पैदा करते है उनकी स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज किसानों की जो पैदावार है उसके दाम नीचे जा रहे है लेकिन दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल चीजें किसान की पैदावार में मदद करती है उनके भाव कम नहीं होते है। खाद का भाव जरूर कुछ कम हुआ जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं लेकिन आप जानते है पिछले दिनों किस प्रकार से बिजली के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े डीजल आयल के दाम बढ़े सिंचाई की दरें बढ़ी हर प्रकार के इंडस्ट्रियल गुड्स और जो किसान के इनपुट्स है उनके दाम बढ़े और किसान उसकी वजह से कांप गया। किसान अपनी पैदावार से सारे देश को खिलाना चाहता है, वह देश को आत्मनिर्भर करना चाहता है, वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रोग्राम को पूरा करना चाहता है, वह चाहता है हमारा देश सुखी और सम्पन्न हो, हमारे देश में ऐसी स्थिति आए जिससे सही तरीके से सस्ते भाव पर लोगों को चीजें पहुंच सकें। लेकिन, श्रीमन्, जो देश की केवल 20 परसेन्ट आबादी है,

[SHRI C. M. STEPHEN in the Chair]

जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उन के लिये किसान सब कुछ मुहैया करे, उन के लिये सारे प्रबन्ध किये जायें, लेकिन किसान की जो चीजें हैं, जो इनपुट्स किसान इस्तेमाल करता है उन के अन्दर कोई सुधार न लाया जाय, इस से बड़ी परेशानी पैदा हो रही है।

15.40 hrs.

श्रीमन्, मैं आप से कहना चाहता हूं-हमारे यहा उत्पादन के हर स्रोत बढ़े हैं, सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ा, लोहे का उत्पादन, बढ़ा, कपडे का उत्पादन बढ़ा, बहुत सी स्कीमे हम ने हैण्डलूम सैक्टर मे शुरू की, ये सब बातें हुई लेकिन आज भी यह स्थिति है कि जो पैदा करने वाला है, वह जिन इनपुट्स को इस्तेमाल करता है, उस को सस्ता नही किया गया---इस मे एक बड़ी बेबसी का आलम पैदा हो गया है। मैं आज आप के जरिये प्लानिग मिनिस्टर साहब श्री गुजराल साहब से कहना चाहता हूं-वे हमारे देश की जो स्थिति है, इस कृषि प्रधान देश की जो स्थिति है उस को जानते हैं---कम से कम वे कोई ऐसी मूल्य नीति बनायें जिस मूल्य नीति के तैहत किसानो को उचित माल मिल सके, उसको उस की मजदूरी मिल सके, देश को सस्ता गल्ला मिल सके और हम अपने भण्डारो को भर सके।

मुझे एक निवेदन और करना है---कल मुझे हैण्डलूम वालो ने यह कहा कि स्टपल यार्न के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फैजाबाद मे एक स्टपल यार्न की फैक्टरी लगाने की बात थी। आप जानते होंगे, श्रीमन, उस फैक्टरी का शिलान्यास भी हो गया था, मशीनें भी आ गई थी, लेकिन अब उस को सूती मिल के रूप मे परिणित किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं---यदि वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पावरलूम्ज और हैण्डलूम्ज को स्टेपल यार्न मिलें तो आप को उस स्टेपल यार्न मिल को सूती मिल के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिये, बल्कि उस को मौका देना चाहिये कि वह स्टेपल यार्न बनाये और जो भाव बढ रहे हैं, उस के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिये, जिस से हम हथकर्घा और पावर-लूम के कारखानों को ठीक तरीके से रामैटीरियल दे सके। मैं यह बात, श्रीमन, इस लिये कह रहा हूं कि हमारे यहां एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नम्बर पर हमारे देश में यही उद्योग आता है---इस लिये इस की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

मैं बहुत शुक्रगुजार हू आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Mr. Chairman, Sir, while I appreciate the spirit in which one of our very esteemed and experienced elders, Shri Bibhuti Mishra, has brought forward this Resolution, I must say that I am speaking on it with some serious reservations. Of course, there is nothing in the Resolution as such which can be opposed. In any case, in the discussions on Private Members' Resolutions and Bills, as I have been saying repeatedly, one does not take a political attitude or a party or partisan attitude and then go on injecting into the debate the traditional party alignments and attitudes.

If you look at the spirit of the Resolution, you will see that, what Shri Bibhuti Mishra wants is effective implementation and timely action, so that the laudable objectives set out by the Government, and in this particular context by the hon. Prime Minister, are not wasted or are not allowed to evaporate. After all, any citizen will judge the State not by what it says but by what it does. All of us say many things, particularly at the time of elections, but it is only one of those many parties, that is, the majority party, that has the opportunity and the responsibility to put into practice what it says at the time of elections or in its election manifesto. Therefore, a period is there---4 years in America for a President

[Shri P. G. Mavalankar]

and five years in our country. This five year term is accepted in our Constitution as a complete term and not more than five years. During that period the Government is to deliver the goods to the common people and if the people see that the goods are not delivered, they would have no faith in the sayings of the government because it is judged by the results. That is why I suppose Mishraji's emphasis is on 'implementation'. The focus is not on the importance of the programme. Anybody in his senses will accept that unless India rises from the economic backwardness, injustice and exploitation, we will not be able to achieve even a measurable success in terms of establishing a just, socialist and egalitarian society. Therefore, I appreciate that the emphasis is on 'implementation' and not on 'emancipation' because 'emancipation' is accepted almost universally by the people of this country.

Then the question arises: if implementation is necessary, how does one go about implementing? Mishraji's resolution, if you read, says:

> "Recommends that necessary steps be taken by the Government."

But I am afraid the resolution itself and even Mishraji's speech which I heard with attention last time, does not tell us in so many words as to what are the specific and concrete steps the Government should take. What these necessary steps are should be spelt out, so that there will then be a more meaningful discussion and debate, whether those steps are right or not, or whether they need to be further strengthened by this or that amendment. My further reservation is on the question of remedy, when the Resolution says, may be taken by the government immediately to remove all legal and administrative hurdles. This is a very dangerous thing because if you say that all legal provisions are hurdles and obstacles, in effect it means you say, 'Let us not rule by law, let us rule by what we think is right, because we have power, we have the authority and, therefore, legal things will not come in our way.' If that is how a government starts functioning, then the implementation would be very fast and very quick, but it may not necessarily be very just and very desirable. Therefore, I would request, with great respect, Mishraji to be cautious of this word 'hurdle' to be used for legal hurdles. I can understand administrative hurdles I can understand administrative bottlenecks because we all know what it means to be held up by bureaucratic delays. Decisions are not taken. Files do not move. Red-tapism grows and, therefore, corruption grows and hence people get frustrated and feel helpless and added to it, there is the political corruption and you get involved in the vicious circle. Therefore, administrative hurdles must go. Administrative bottlenecks must go. The bureaucracy must be attuned to the new social purpose for which they are meant to function as civil servants at various levels. Therefore, if the hurdle is administrative inaction or slow action or unwillingness on the part of the administration, I am all for Mishraji's point when he says that these hurdles must go

But when you talk of legal hurdles, I begin to feel suspicious because it would mean that you want to get rid of the principles of Rule of Law and you do not want any legal provision and legal safety against possible misuse and abuse at various stages of implementation.

Then, Sir, one or two more points and I have done. The whole point is that this implementation is so slow not only because of administrative bottlenecks and occasionally some legal difficulties, but because, by and large, we lack the political will to put into practice what we honestly believe we ought to put into practice. To-day, I am speaking on Mahatma Gandhi's martyrdom day and the martyrdom of those who fought for

the independence of India. We started the day by observing silence in the morning.

My own Resolution has been listed to-day. I do not know whether I will get a chance to move it.

Let us remember Gandhiji. Let us remember Gandhiji by putting at least something in practice what he had been sincerely believing in. If we believe that with economic justice, social justice, there can be a just, egalitarian and an ideal society, for which we went to strive, then where is the hurdle? Hurdle is not so much in the bottlenecks in administration, it is not so much in terms of legal administration, but it is in terms of lack of will and lack of earnestness. Sometimes, I feel that no one, at certain levels, including Members of Parliament and the members of the State legislative bodies, is earnest about anything. We say a lot, But when it comes to an action, we are falling short of action. The sincerity of purpose is missing.

To conclude, therefore, I would say that if people are able to see and enjoy the benefits and fruits of the programme, they will feel involved and it is only when people are encouraged to participate enthusiastically at all levels in the programme, I am sure the new Planning Minister will agree with me, that ultimately all planning will succeed. It will be possible only if people participate by way of meaningful involvement. People are ready to go by any Government statement if that Government's statement is followed by Government's honest and sincere action. What we see today is this: promises and more promises, slogans and more slogans, paper work and more paper work—this is the order of the day! Let us get rid of it and at least on this day of 30th January, re-dedicate ourselves to the very relevant and refreshing message of Mahatma Gandhi and begin to implement the same ourselves as individuals and as citizens of this country. We may be so as responsible men of affairs in this country, marching in the direction of creating an economically just and socially egalitarian society in our country.

**श्री चन्द्र भाल मणी तिवारी** (बलरामपुर): सभापति जी, आप ने मुझे समय दिया है, इस के लिए मैं आप का आभारी हूं।

आज हमें इस बात पर गौर करना है कि हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उस में कुछ तरक्की हो रही है या नहीं, जो सोचा गया था उस पर अमल हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं निराशा के साथ कहना हूं कि छः महीने बीत गये हैं लेकिन अभी उस पर 5 परसेन्ट भी अमल नहीं हुआ है। इसलिये जो कार्यकाल इस के लिए निश्चित किया गया हो उस में 5 परसेन्ट की तरक्की भी न हो, तो भविष्य में क्या हो सकता है। इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो आर्थिक प्रोग्राम है, उस में खास तौर से यह रखा गया है कि देश की तरक्की के सारे साधन जुटाए जाएं, लेकिन मैं जानता हूं कि साधन जुटाने के नाम पर कुछ ज्यादा खर्च करने की बात हमारी ब्योरोक्रेसी बनाती है, उन के संसाधन के लिए सब खर्च हुआ है लेकिन फील्ड में उस का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। हां, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं उन को जरूर फायदा हुआ है लेकिन उन की संख्या बहुत कम है। तो मैं अपने प्लानिंग कमीशन को, अपने प्लानिंग मिनिस्टर को उस से जागरूक करना चाहता हूं कि वह जो अवव्यवस्था बनाई जा रही है, उस से अपने को बचाएं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस में कुछ क्षेत्रीयता की बात भी आनी चाहिए। कुछ क्षेत्र बहुत डेवलप्ड हैं और कुछ अनडेवलप्ड है और जो एरियाज खास तौर से अनडेवलप्ड हैं, उन की ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। वहां की समस्याओं को देखें और

[श्री चन्द्र भाल बली तिवारी]

उन के निवारण के लिए क्या रास्ता अपनाया जा सकता है जिस से उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का भला हो सके, और समाज और देश का कल्याण हो सके इस को देखें इस मे दो तीन चीजे हैं, जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जैसे कि कोई एरिया अगर डेवलप्ड नही है, तो इस का कारण क्या हो सकता है। इस का कारण यह हो सकता है कि वहां पर बिजली नही है पानी नही है और इरीगेशन नही है। ये बुनियादी सवाल है। इन बुनियादी सवालो को हल करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले साल हम ने देखा है कि बिजली और सिंचाई के लिए विशेष पैसे का प्रावधान किया गया था लेकिन आज भी नतीजा कुछ वैसा ही पडा हुआ है कि कागजो मे तो यह है लेकिन उस को करने के लिए कार्यक्रम नही निश्चित किये गये है और अगर कही कार्यक्रम निश्चित भी किये गये है तो उन पर अमल नहीं किया गया है। जो प्रोग्राम आप ने बनाया है उस को कार्यन्वित करने के लिए आप सक्रिय कदम उठाए। मेरा आप से इतना ही निवेदन है।

16 hrs.

**श्री आर० डी० बड़े** (खरगोन) विभूति मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है इसका मैं समर्थन करता हू। इस प्रस्ताव को चूकि आपने रखा है इस वास्ते हमे इस पर बोलने का चास मिल गया है। 1962 मे आपने भूमिहीनो को भूमि देने का नारा लगाया था। लेकिन भूमि कहां दनी है यह आपने नही बताया था और आपने उनको भूमि नही दी। मैं मध्य प्रदेश के सवाल को ही आपके सामने रखना चाहता हूं। वहा हजारो साल से जंगल खाली पडे हुए है। वहा पर लोगो से जगल काट कर पैसे ले लिए फिर और जमीन दे दी। लोगों ने ट्रेक्टर बना दिए। आपने सब जला डाले। इससे लोगों को एक करोड का नुकसान हो गया। तलवारें तैयार करके आपने उनको काट डाला, फलसे काट डाली और लोगों को नुकसान हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1962 के चुनाव में आप हार गए और जनसंघ जीत गया। हमने आदिवासियों को जमीन जंगलों की देने के लिए कहा। अब बीस सूत्री कार्यक्रम आया है तब आपने लोगों को जमीने देनी शुरू की। आदिवासियों को भी मिलनी शुरु हो गई हैं। कम से कम 36,000 लोगों को आप लाख डेढ लाख हेक्टेयर जमीन देने जा रहे हैं। पहले जहा आपने कहा था कि जंगल की जमीन नही मिलेगी, अब उसी जमीन को आप देने जा रहे हैं। इससे लोगों का फायदा होगा। अब महाजन ने भी जो 20–25 साल तक उसकी जमीन को दबा करके रख छोडा था उससे उस जमीन को ले कर आप उसको दिलवाने जा रहे है। अब आपकी आखें खुली है कि उनको खेती के लिए तथा रहने के लिए जमीन मिलनी चाहिए और मिलनी शुरु हो गई है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि लीगल हर्डल्ज नही होनी चाहिये। चूकि लीगल हर्डल्ज को निकाल दिया है इस वास्ते भूमिहोनो को, आदिवासियो को भूमि मिलनी शुरु हो गई है।

मध्य प्रदेश मे आदिवासी कमीशन नियुक्त हुआ था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको किया था। मै भी उसका एक मेम्बर था। मैंने राज्य का दौरा किया। दौरा करने के बाद मैंने देखा कि वहा आदिवासियों को बंधक मजदूरो की तरह रखा जाता था। अगर किसी ने दो ढाई सौ रुपया ले लिए तो जब तक वह उनको उतार नही देता था तब तक उसको बधक मजदूर के तौर पर काम करना पड़ता था। रायपुर मे परिस्थितियां अलग थी। आगे जाए तो भोपाल मे आपको अलग परिस्थितिया मिलेंगी। वहां आदिवासी अलग है। इधर भील जाती के आदिवासी लोग है। अब तो आपने बंधक मजदूरी को समाप्त कर दिया है। अब उनको कम से कम जमीन भी मिलने वाली है। इन बंधक मजदूरों को गुलामों की तरह से

रखा जाता था। एक महाजन ने एक पत्र अगर उससे लिखवा लिया कि उसने दो सौ रुपये लिए हैं तो वह उसको छोड कर कही दूसरी जगह जा नही सकता है और अगर जाता है तो जिस के पास वह जाता है उसको लिख कर देना पडता है कि वह रुपये देगा। रायपुर के लड़के जबलपुर कर्जा उतारने के लिए साइकल रिक्शा ड्राइवर का जा कर काम करते हैं खरगोन में भीलों की हालत यह है कि एक दफा वे कांट्रेक्ट कर लेते है तो जब तक वह काट्रेक्ट पूरा नही हो जाता है वे दूसरी जगह जा नही सकते हे। इस प्रकार की वहा गुलाम प्रथा है। एक आदिवासी की लडकी किसी जगह काम करती है, जहां वह काम करती है अगर उस की लडकी की शादी हो जाती है, तो आदिवासी को अपनी लडकी को भी उसके साथ भेजना पडता है उनकी सेवा छूट नही सकती है। यह जो बॉडेड मजदूरी चल रही थी, उसमे 20 सूत्री कार्यक्रम से हमारे यहा के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है।

हम 20 सूत्री कामों की पहले से मांग करते थे, अब काग्रेस वालो ने इसे शुरू किया है। भूमिहीनो को भूमि देने से और बंधक मजदूरी समाप्त करने से लोगो को फायदा हो रहा है, इस लिये मे इसका समर्थन करता हू।

**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (मछली शहर): सभापति महोदय, माननीय श्री विभूति मिश्र ने जो यह प्रस्ताव रखा है, मैं इसका हृदय से समर्थन कर रहा हु। मुख्य बात मिश्र जी के प्रस्ताव मे यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के लागू करने मे जहा तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, उनमे तो बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन प्रान्तीय स्तर, जिला स्तर और इलाक स्तर पर इनकी कार्यान्वित ठीक से नही हो रही है। यह कहने के लिये तो है लेकिन उस पर ठीक से अमल नही किया जा रहा है। जब तक इस पर नीचे के स्तर पर अमल नहीं होगा तब तक हम इसका लाभ नही उठा सकते है।

20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा देश में आपात्कालीन स्थिति की घोषणों के तुरन्त बाद की गई। देश में जैसी परिस्थितियां हो गई थीं उससे वातावरण बहुत दूषित हो गया था और सभी में एक तरह से बेचैनी पैदा हो गई थी? स्कूल कालेज ठीक से नही चल पा रह थे, हडतालें हो रही थी? जिन लोगो के चोरी डकैती मे वॉरेन्ट कटे हुए थे, वे लोग कचहरी में पहुंचकर मिजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठ कर कहते थे कि न्यायधीश हम हैं। विद्यार्थी वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठकर कहते थे कि हम वाइस-चांसलर हैं, और वह आदेश पास करते थे। जो लोग बिना टिकट के चलते थे वे मनमानी तौर पर अपने घर के पास जंजीर खीच लेते थे और गाडी रुक जाती थी। सामान के रहते इनकार कर दिया जाता था कि सामान नही है, मन माने दाम पर बेचा जा रहा था। अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी मालूम होता था कि कोई शासन ही नही चल रहा है। ऐसी परिस्थिति मे जब आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई, उसी के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम की भी घोषणा की गई कि हमको क्या करना है। उसी दिशा मे जो प्रयास हुए है, उन से हर क्षेत्र में लाभ हुआ है और बडा व्यापक लाभ हुआ है लेकिन जहा तक उसके नीचे के स्तर पर अमल करने की बात है, कहने के लिये तो नीचे के अधिकारी इस बात को कहते हैं कि हम 20-सूत्री कार्यक्रम को मानेंगे और इस बारे मे बहुत से प्रस्ताव होते है लेकिन सचमुच जितना कहा जाता है, अगर 50 प्रतिशत भी काम पूरा किया जाये तो देश की स्थिति मे बहुत कुछ सुधार हो सकता है।

इस कार्यक्रम के लागू करने में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि देश का नीचे का वर्ग जो गरीब है, भूमिहीन है, किसान है, खेतिहर मजदूर है उनको जमीन देने की बात है। धीरे-धीरे परिस्थिति ऐसी होती जा रही है कि

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

जमीन की सीलिंग द्वारा छोटे-छोटे काश्तकारों को खेती के अच्छे साधन मिलने से वे मजदूर को नहीं रखना चाहेंगे। तो जो आदमी मजदूरी पर ही गुजर कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है कि वह रोजगार कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, नौकरी दिलवा सके तो उनके सामने समस्या पैदा हो रही है कि अगर वह जमीन की मजदूरी नहीं पायेगा तो कहां जायेगा। ऐसे आदमी को अगर जमीन दे दी जाती है तो कम-से-कम उसकी आजीविका का साधन हो जाता है। सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं, उससे बड़ी तेजी से काम हुआ है, जमीन का बटवारा तेजी से हुआ है। कुछ लोगों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है लेकिन जो सावधानी बरती जा रही है, उसमें उनको जरूर जमीन मिल जायेगी और वह कब्जा पा लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग थे, जो अपनी जमीन पर नहीं, बल्कि दूसरे की जमीन पर बसे हुए थे। जमीन के मालिक उन को आये-दिन धमकिया दिया करते थे। 20-सूत्री कार्यक्रम में उन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने की बात कही गई है। उन में से बहुत से लोगों को आवास मिल रहा है। लेकिन इस में एक परेशानी यह हो रही है कि जमीन कम होने के कारण कहीं कहीं आबादी से दूर जमीन दी जा रही है। अकेला आदमी वहां जाना पसंद नहीं करेगा। यदि आबादी में दूर जगह उपलब्ध है, तो उन लोगों को सामूहिक रूप से वहां बसाना चाहिए। अगर एक दो आदमियों को जमीन देनी है, तो उन्हें आबादी के नजदीक ही दी जाये।

यह बड़ी खुशी की बात है कि चीजों के भाव कुछ कम हुए हैं। पहले दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे थे, उस से लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी। हम देखते हैं कि किसानों के उत्पादन की चीजों की कीमत तो ज्यादा गिरी है, लेकिन कल-कारखानों में पैदा की गई चीजों की कीमत में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए, जिस से किसानों द्वारा पैदा की गई चीजों और कल-कारखानों में पैदा की गई चीजों भाव संतुलित रह सकें।

किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 50 लाख हैक्टर नई जमीन की सिंचाई की व्यवस्था करना तय किया है। यह सब काम प्रान्तीय स्तर पर किया जाता है। पता नहीं, अभी तक नलकूप और नहरें आदि बनाने की दिशा में क्या प्रयास किया गया है। हमें उत्तर प्रदेश का अनुभव है कि जो पुराने नलकूप बने हुए थे वे ज्यादातर खराब हालत में पड़े हुए हैं, उन में सुधार नहीं हो पा रहा है, सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है और नई भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करने में दिक्कत आ रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान उस तरफ जाये। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा हुआ था। वहां खेती पर ही अधिक लोग बसे हुए हैं और खेती का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए वहां की सिंचाई की सुविधा के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।

जहां तक बंधक प्रथा का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में बहुत से लोगों ने थोड़े पैसे दे कर मजदूरों को फंसा रखा था और वे उन से पुश्त-दर-पुश्त काम लेते थे। सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाया है, उस से उन लोगों का उद्धार हुआ है।

सरकार का यह कदम भी बहुत सराहनीय है।

मैं एप्रेन्टिस योजना के लिए भी सरकार की प्रशंसा करना चाहता हू। आज पढ़े-लिखे लोगो को बेकारी का सामना करना पड रहा है। उन्हे नौकरी के लिए जगह जगह ठोकर खानी पडती है। सरकार ने इस योजना को प्रारम्भ कर के अच्छा किया है। सरकार को इस दिशा मे ठोम कदम उठाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगो को काम मिल जायें। अगर इस समस्या का समाधान हो जाये, तो एक बडी भारी परेशानी दूर होगी। और बहुत से लोगो को जीविका का साधन मिल जायेगा।

इन शब्दो के साथ मै श्री मिश्र के प्रस्ताव का समर्थन करता हू।

**श्री कमला मिश्र "मधुकर"** (केमरिया) सभापति महोदय, मैं श्री विभूति मिश्र को इस बात के लिए धन्यवाद देता हू कि उन्होने अपने प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर खीचा है कि 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने मे बहुत सी कठिनाइया हो रही है। 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे मे मेरी पार्टी के विचार बहुत बार व्यक्त किये गये है। मैं समझता हू कि 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा से देश मे एक नई आशा जगी, उत्साह का प्रादुर्भाव हुआ, नई चेतना जगी और हम लोगो ने समझा कि देश को एक कदम आगे ले जाने मे यह कार्यक्रम कारगर होगा। इसलिए हमारी पार्टी और हम उस का तहे-दिल से समर्थन करते है। लेकिन हम चाहते है कि इस को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाये, जो इस समय नही हो रहा है। मैं बिहार और अपने जिले के उदाहरण से दो तीन मुख्य बातो की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले मैं एक पत्र उद्धृत करूंगा जो हमारी पार्टी के बिहार राज्य शाखा के मंत्री श्री जगन्नाथ सरकार ने बिहार के मुख्य मंत्री के नाम भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है:

"Reports submitted by the Government to the State-level Implementation Committee have admitted that the pace of implementation, particularly items concerning land reforms, has been tardy. It is incumbent upon all those who stand for the well-being of the people to do everything possible to expedite the pace of implementation."

यह हमारी पार्टी के मंत्री ने बिहार के मुख्य मंत्री के नाम लिखा है और यह सुन कर आप को आश्चर्य होगा क्योंकि केरल का अनुभव नही है आपको, बिहार में यह हो रहा है कि अंचल लेवल पर और पचायत लेवल पर जिन लोगो को कार्यान्वयन समितियो मे लेना चाहिए इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए उन की अवहेलना की जा रही है और यह प्रोग्राम जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है इस मे पार्टीबाजी की जा रही है। यानी अंचल लेवल पर और ग्राम पचायत लेवल पर कार्यान्वयन समितियो मे जो कायम की जा रही है मुख्य मंत्री का एलान है कि सी० पी० आई० के लोगो को नही लेने चाहिए। मैं समझता हू कि जिन पार्टियो ने 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है उन को न लेने से यह कार्यक्रम कैसे लागू हो सकेगा? यह प्रोग्राम यद्यपि अच्छा प्रोग्राम है लेकिन नौकरशाही पर अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए निर्भर करता है और आप इस चीज को देखिए, बिहार मे लैण्ड के इम्प्लीमेंटेशन के सवाल को ही लीजिए, बिहार में जमीन का कोई रेकार्ड नही है। सरकार ने एलान किया है कि उस के पास कोई रेकार्ड ही नहीं है। इस के अलावा इस एलान के बाद जो नये नये लोग कांग्रेस में

[श्री कमला मिश्र "मधुकर"]

आ रहे हैं और कुछ पहले के कांग्रेसी भी इसमें बाधा डाल रहे हैं। वस्टेड इन्टेरेस्ट के लोग हैं जो नहीं चाहते कि प्रोग्राम लागू हो। वह चाहते हैं कि यह प्रोग्राम फेल हो जिस से जो असंतोष पहले चल रहा था वह असंतोष फिर से फैले। वे लोग भीतर-घात कर रहे हैं। आप को मालूम होना चाहिए कि बिहार में कांग्रेस के ही टिकट पर जीते हुए श्री दिनेशसिंह हैं, जिन की चार हजार एकड़ जमीन नामी वहां है। यह चीज सरकार की नोटिस में भी आ चुकी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यह कह रहा हूं कि बिहार में 20 सूत्री कार्यक्रम ठीक तरह से लागू नहीं हो रहा है और उस के लिए बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। वह लोग इस कार्यक्रम को लागू करने में फेल हो रहे हैं और इस के लागू नहीं होने का मतलब क्या होगा? बिहार में ही जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन शुरू हुआ था यह आप जानते हैं।

बंधुवा मजदूरों का जहां तक सवाल है बिहार के मुख्य मंत्रीने एलान कर दिया कि बिहार में यह व्यवस्था ही नहीं रही है। आश्चर्य होता है इस बात पर। इस बात को हमारे नेताओं ने रेफ्यूट किया है। श्री भोगेन्द्र झा ने खुद लिखा है कि यह बातें बिल्कुल झूठी हैं। उन्होंने चैलेंज किया है कि अपने गांव में और हमारे गांव में चल कर जांच कीजिए कि यह बंधुवा मजदूरों की प्रथा है या नहीं। मैं अपने जिले चम्पारन की बात जानता हूं कि हमारे जिले में यह प्रथा चल रही है या नहीं। बिहार के मधुबनी जिले का एक गांव है कोइलख, राजनगर ब्लाक में जहां के एक भूमिहीन मजदूर ने जब प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम का एलान सुना तो वह खुशी के मारे नाच उठा और उसने अपने जमींदार के यहां जा कर कहा कि हम को पूरा अधिकार मिलना चाहिए और पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। उस का नतीजा यह हुआ कि उसकी वहां पिटाई हुई और उसका घर उजाड़ दिया गया। फिर पंचायत हुई, उन में भी कोई निपटारा नहीं हुआ। थाने वालों ने केस दर्ज नहीं किया क्योंकि बिहार सरकार का एलान है कि बिहार में बंधुवा मजदूर नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो वहां भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। प्रधान मंत्री के ऐलान के बाद भी अगर यह कार्यक्रम फेल होने जा रहा है तो स्थिति भयंकर होगी।

एक निवेदन मेरा यह है कि देहाती क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के रहने की व्यवस्था की जाय। मैं दो तीन प्वाइंटस उठा रहा हूं। क्या जमीनों के कुछ टुकड़े देने से उन भूमिहीनों की समस्यायें हल हो जायेंगी। मैं जानता हूं आपने यह प्रशंसनीय काम किया है लेकिन क्या यह काम बिहार और दूसरे राज्यों में हो सकता है? यदि हो सकता है तो फिर वहां पर वह क्यों नहीं हो रहा है—इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रधान मंत्री जी का यह ऐलान है कि बीस लाख हेक्टर में सिंचाई की नई सुविधायें बढ़ाई जायेंगी लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? वहां पर गण्डक प्रोजेक्ट और कोसी प्रोजेक्ट की योजनायें हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन बहुत धीमी गति से हो रहा है। वहां पर इतना करप्शन है जिसके चलते गण्डक प्रोजेक्ट जो 56 करोड़ का था उस पर 120 करोड़ खर्चा होने के बाद भी यह मालूम नहीं कि वह कब तक पूरा होगा। वहां पर जो पानी का जमाव होता है उसकी निकासी की योजना को भी लागू नहीं किया जा रहा है। जिन इलाकों में गण्डक का पानी नहीं जायेगा वहां पर

छोटे छोटे ट्यूबवेल लगा कर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन इस काम में कोई तेजी नहीं लायी जा रही है। बीस-सूत्री कार्यक्रम में बिजली का विकास भी शामिल है। सौभाग्य से बिजली मंत्री यहां पर बैठे हैं उनको मालूम है बिहार में, खासकर उत्तर बिहार में बिजली के विकास के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं। प्लानिंग कमीशन ने बिहार बिजली बोर्ड को सुझाव दिए हैं, मुझे पता नहीं बिहार सरकार ने उस पर क्या रेस्पांस दिया है और कौन से सुधार किए गए हैं। जिस प्रकार से यहां केन्द्र ने रेलवे बोर्ड की शिकायत होती है उससे गई गुजरी स्थिति बिहार बिजली बोर्ड की है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है हालांकि बिजली विभाग भी मुख्य मंत्री के हाथ में ही है। तो बीस सूत्री कार्यक्रम ने जो आशायें जगाई हैं उसकी हम तारीफ कर सकते हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आज नौकरशाही का जो बोल बाला है उसको समाप्त होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पंचायत लेविल से लेकर ऊंची सतह तक हर लेविल पर कमेटीज बनाई जाये और उसमें उन लोगों को सम्मिलित किया जाये जिनको कि इस पर दिल से विश्वास है। इस प्रकार जो कमेटियां बनाई जाये उनके जरिए से समय समय पर इसके इम्प्लीमेंटेशन को रेव्यू किया जाये, मूल्यांकन किया जाये कि कार्यक्रम पूरे हुए या नहीं।

आज अफसरशाही की जो हालत है, मेरे जिले में ही एक शिक्षक महोदय, जो कि हेडमास्टर हैं उनकी घटना मैंने आपको सुनाई थी कि उन्होंने बीस-सूत्री कार्यक्रम का प्रचार किया तो उनको डी आई आर में बन्द करने की योजना बना दी गई क्योंकि कलक्टर साहब उनसे नाराज थे। मैं खुले आम कहना चाहता हूं कि नौकरशाही के बल पर यह कार्यक्रम पूरा होने वाला नहीं है, इसमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो अधिकारीगण इस कार्यक्रम के प्रति विश्वासघात करना चाहते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं जानता हूं आंचलिक अधिकारी जमींदारों से घूस लेते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उनकी जमीनें नहीं निकलती हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि किसी भी पार्टी के आदमी हों, वह पहले अपनी जमीनें निकालने के लिए आगे आयें। यदि मंत्री लोगों से इसकी शुरुआत हो तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इसके लिए एक पावरफुल मास मूवमेन्ट, विशाल जनता का आन्दोलन शुरू होना चाहिए जिससे जनता यह समझे कि एक अभियान शुरू हुआ है। इस तरह से इसको लागू करने के लिए जनता में एक चेतना जगानी होगी।

जैसा कि श्री नरसिंह नारायण पांडे जी ने अभी यहां पर कहा था कि किसानों के उत्पादन की कीमतें गिर रही हैं लेकिन जो किसानों के इनपुट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं जिससे किसानों में असंतोष की भावना पैदा हो रही है। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि जो किसानों की जरूरत की चीजें हैं जैसे खाद, बीज, बिजली, पानी, कर्ज और दूसरे इनपुट्स ट्रैक्टर, दवायें वगैरह उनके भाव भी घटने चाहिए ताकि किसान की पैदावार और इन चीजों के भावों में बेलेंस रहे। ताकि किसानों को जो चीज वे पैदा करें उस का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी यह विश्वास हो कि उन को भी चीजें ठीक दामों पर मिलेंगी। यदि इन बातों का ध्यान रखा जायगा तो यह बीस-सूत्री कार्यक्रम सफल होगा, इस के प्रति केन्द्रीय सरकार

[श्री कमला मिश्र 'मधुकर']

की जिम्मेवारी है, क्योंकि यह प्रधान मंत्री जी का ऐलान है। केन्द्र यदि यह समझे कि राज्य सरकारें करेंगी तो काम नही होगा। मेरी आप से अपील है कि केन्द्रीय सरकार इस बात की जांच करे कि किस राज्य मे इम्प्लीमेन्टेशन नही हो रहा है। जहां इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है, वहां देखा जाय कि किन कारणो से नही हो रहा है तथा उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाय।

**श्री बी० आर० शुक्ल** (बहराइच) सभापति जी, बीस सूत्री कार्यक्रम के ऐलान से देश मे एक नई जाग्रति, नई उमग और नई आशायें जन-जीवन मे पैदा हुई है। हमारे सम्मानित सदस्य श्री मिश्र जी ने, जो कि एक असलियतपसन्द गाधीवादी हैं, ग्रामीण जनता की समस्यायो से भलीभाति परिचित है, उन्होने इस प्रस्ताव को रख कर इस सदन को जो चर्चा का अवसर दिया, उस के लिए हम सब लोग उन के बहुत आभारी है। इस समय तो वातावरण ऐसा हो गया है—जैसे हमारे हिन्दू समाज मे किसी पूजा का शुभारम्भ तब तक नही होता है, जब तक श्रीगणेशाय नम न किया जाय। इस लिए बीस सूत्री कार्यक्रम का जहा तक सम्बन्ध है चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे जमाखोर हो, चाहे तस्कर समाज हो, सब इस का स्वागत करते है। अब देखना यह है कि इस को किस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं निराशावादियो मे से नही हू, लेकिन साथ ही साथ उन आशावादियो मे भी नही हू जो यह समझे कि सब कुछ इस प्रोग्राम के ऐलान से ही हो जायगा। सब से बडी देश की समस्या जो देहातो से सम्बन्धित है, वह यह है कि खेतों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिलने की सुविधा हो। मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि पिछडे क्षेत्रो मे सिंचाई की व्यवस्था बिलकुल नगण्यप्राय है, इस दिशा में बहुत कम काम हुआ है। अब भी यहां पर इस ओर ध्यान दिलाया जाता है तो केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर छोड़ देती है। राज्य सरकारें कहती है कि केन्द्र सरकार हम को रुपया नहीं देती है—इस दोअमली हुकूमत की वजह से काम नही हो पा रहा है। जो पिछडे क्षेत्र हैं, खास तौर से वह ज़िला जिस का मैं प्रतिनिधित्व करता हू—बहराइच जिला—जो नेपाल की सीमा पर है, वहा सिंचाई का कोई साधन नही है। इस देश मे इस बात का लक्ष्य होना चाहिए कि अन्न केवल पेट पालने के लिए ही पैदा नही करना है, बल्कि इस धरती से अन्न पैदा कर के हम बाहर भी भेज सके, हमारे अन्य देश है, जहा अन्न नही होता है, अन्य देश है जहा हम इस को भेज सकते हैं। हमारे यहा खेती का धन्धा इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिस से उत्पादन का निर्यात हो सके।

दूसरी बात—हमारे यहा जगलो मे जो भूमि होती है जिस को टागिया फारेस्ट कहते है वहा लोगो को पौदे लगाने के लिए और खेती के लिए जमीन दी जाती है। लेकिन वहा के अधिकारी रिश्वत लेकर उस जमीन को धनी मानी लोगो को दे देते है और भूमिहीनो का वह जमीन नही दी जाती है। इस तरफ आप को शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

तीसरी चीज—यह कहा गया है कि ग्रामीण बैंक काफी काम कर रहे है उन को और ज्यादा खोलने की व्यवस्था हो रही है। मैं अभी हाल मे चण्डीगढ सेशन में गया था वहा एक स्कूटरवाले से मैने पूछा कि क्या तुम स्कूटर के मालिक हो या किराये पर चलाते हो। उस ने कहा किराये पर चलाता हू आधे से ज्यादा मजदूरी मालिक ले लेता है। मैंने कहा तुम बैंक से कर्जा

क्यों नहीं लेते हो ! उस ने कहा वहां जाते है तो कर्जा नहीं मिलता । आप चाहे जितना प्रचार करे, उस से काम नहीं चलेगा आज ऐसे बहुत से रिक्शेवाले और स्कूटर वाले है जिन के पास अपने स्वय के रिक्शा या स्कूटर नही है आप उन को लोन देकर उन को स्कूटर या रिक्शा उपलब्ध कराये ।

चौथी चीज यह है कि बधुआ मजदूरो को आप ने लिबरेट किया छोटे तबके लोगों के कर्ज को माफ किया लेकिन आप ने उन के कर्ज की क्या व्यवस्था की ? अगर एक आदमी मर जाता है और पैसे की जरूरत होती है तो उस को पैसा नही मिलेगा । आप के बैंक तो खेती के लिये कर्जा देते हैं लेकिन किसान की और भी तो जरुरते है जैसे लडको को पढाना, लडकी की शादी करना आदि । इन सब बातो के लिये व्यवस्था होनी चाहिये और अगर यह नही है तो यह आप के बैंक उनकी जरूरतो को पूरा नही कर पायेगें, और फिर इन लोगो को झक मार कर कर्जा उन्ही लोगो से लेना होगा जो पहले भी देहात मे इन का खून चूसते रहे हैं । जिस को पैसे की आवश्यकता पडेगी वह फिर गाव के साहूकार के पास जायेगा । तो इन सब बातो पर व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिये । इतने थोडे समय मे और क्या कहू–मै तो यही चाहता हू कि एक वातावरण इस प्रकार का जन-जागरण देश मे पैदा हो और कार्यान्वयन समितिया हर जिले मे बननी चाहिये जो इस प्रोग्राम के इमप्लीमेंटेशन को देखें । आधिकाश भागो मे इमप्लीमेंटेशन कमेटिया नही बन पायी है और जहा बनी भी है उन मे जो लोग रखे जा रहे है चाहे हमारी पार्टी के हो या दूसरी पार्टियो के वही प्रतिक्रियावादी है फासिस्ट मनोवृत्ति वाले हैं जिन को इस मे विश्वास नही है । इसलिये इस मे बहुत छानबीन कर के कार्यान्वयन समितिया बनायी जानी चाहियें । वर्ना और जैसे जैसे नारे लगाये गये और उस का कार्यान्वयन नही हुआ वही दशा इस की हो जायगी ।

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Sir, while supporting the resolution moved by Shri Bibhuti Mishra, I want to make a few suggestions. I generally agree with what he has said. We have to appreciate the achievements of the country, particularly in the field of agriculture. In spite of administrative hurdles and other setbacks, our agriculturists have sacrificed a lot for our country Even before independence, they were exploited. Even after independence, unfortunately, this Government has not given proper assistance to the agriculturists for development of agriculture, which is the basic industry of the country. There is no use lecturing here about 20 point programme and other programmes. The question is, how far have we implemented them? You should remove the administrative hurdles and create confidence among the agriculturists With all good intention and sincerity, our Prime Minister has come forward with this programme This should be properly implemented by removing the administrative and other hurdles. It is no use passing resolutions here as the zila parishads or panchayats do. The object of the mover of this resolution is that the 20-Point Programme should be implemented speedily. People only want that and they are waiting for the implementation. The prices of all the inputs that the agriculturist requires have gone up, but there is no guarantee about the price of what he produces. Even Mahatma Gandhi said, farmers are producing and the bureaucratic and other people in the cities are eating. These Super Bazars are meant only for city fellows. If you simply go in a car, how do you know as to what are the prices prevailing in the market. Why don't you ask the producers to open their shops? In Madras, when Shri Prakasam was the Chief Minister, he had

[Shri K. Suryanarayana]

forced the producers and manufacturers to open their own shops—producers cum consumers cooperative societies Mr. Gujral, I want that all the producers and manufacturers should open their fair price shops.

In my area, the rice prices are less than the Food Corporation prices by Rs 30/- per bag. They wanted to create price equalisation in regard to sugar. We are not dying without sugar. Let there be equalisation for all foodgrain prices throughout the country In Andhra Pradesh, rice is being sold at much below the price prevailing in other States. Kerala wanted to purchase rice from us but you are not allowing.

I would appeal to the Prime Minister through Shri Gujral to open more producers cum consumer societies

I want to suggest to the Members that they should not only make suggestions but they should search their own hearts to see for themselves as to how much they have served the people What is the use of giving lectures here and taking Rs. 51/-. Our leaders should also see how many projects they have created, how many they have implemented If we all see these things and put our heart and soul in the programme, only then the real success will emerge

One more thing I want to suggest. Whatever we spoke should be published, because our constituents are not sitting here and they are not listening to us. Therefore, I want to appeal to the Chair and the Speaker that whatever is spoken here, should be published if it is not objectionable. Please include this point also in the 20-Point Programme.

SHRI SYED AHMED AGA (Baramula): Mr. Chairman, Sir, this 20-Point Programme is not something that has come suddenly. It is the continuation of the projection of the same policies which our Prime Minister initiated a decade ago. Our object is to reduce the gap between the rich and the poor. We abolished the privy purses because we wanted the Maharajahs to become commoners. All that has come about. Of course, we had difficulties. We now have the 20-Point Programme. Hurdles should not be brought in, in the way of implementation of this programme which has raised hopes in the minds of the entire population. Our population is 60 crores. The hopes of our population should be allowed to be achieved. In regard to land reforms, the court should not come in the way of their implementation In this country where 47 per cent of the population lives below the subsistence level, we have also to look to 2 or 3 things For example in regard to essential articles, people must have the purchasing power to purchase these. Those essentials must be made available to them by a little reduction in prices here and there It is not enough if this is done in the case of items used by the middle class people We have to see that the prices of the essential required by the common man are reasonable enough, so that he can buy them. The distribution of commodities which are essential for living should be under the control of the Government and not left to the private sector which would be interested only in making profits It must be controlled. If Government cannot attend to distribution and take it over themselves, they should allow and develop consumer cooperatives who can do this work But distribution should also be very effective, so that the common man gets the essential commodities. Hoarding and black-marketing should not be tolerated as far as essential are concerned. Let us now take food. In regard to food, we took over the wholesale trade, but later we said we will take

over the marketed surplus only. We then said that we would not be able to do it. Even in a year when we have a bumper crop, we must take over the entire marketable surplus; it should be with the Government, so that it is not available to the hoarder and the black-marketeer to speculate upon and the producer also is able to get a proper price. Because of bumper crop, imports etc., prices should not fall below a certain level. It is not very difficult to do this. It can be done by giving the producer credit throughout the year and then taking the marketable surplus from the standing crop. There should not be any difficulty. This has worked very well in many places. I do not accept that it is difficult, because I have done it myself.

Now about Kashmir, because I belong to that State. In Kashmir, we have an abundance of fruits; but small producers own 1, 2 or 3 trees. You cannot leave it to the poor producer to sell it. He cannot do any marketing there. Government must also take up the processing of the fruits in my State, because it is not possible for the private sector to do it The private sector is interested only in doing its own business. But what the Government is expected to do is to deal with those who own only one, two or three tree and who cannot sell their produce. They have to take his produce, process it and sell it.

Another aspect is craftsmanship, which is also included in the 20-Point Programme. There are two aspects. One is the economically pitiable condition of the craftsmen, and the other is the employment aspect. Taking the example of Kashmir again take carpet-weaving. It is true that Iran is well-known for carpet-weaving. But we have beaten Iran in carpet-weaving. So, our country should be proud that Kashmir has acquired that much of proficiency. We can sell carpets in the world market, and it is very important and necessary. But that we will be able to do only if we strengthen the industry and have looms for making more carpets. It will help us not only to earn foreign exchange but also to provide employment. While talking of employment, it is not enough to provide employment to a few young graduates and then say that we have done a lot. In Kashmir the position is that most of the workers do work only for three or four months. The rest of the period they just sit down and do nothing because they cannot do anything outside on account of the weather. But they can certainly do carpet-weaving, which is inside the house, which is not affected by the weather. In that way, they can earn their livelihood and also help the country to earn foreign exchange I cannot appreciate any excuse for not doing this But this can be done only by the Central Government. They have to provide the necessary funds and, if necessary, even compel the State Government to encourage this cottage industry.

Then I come to hondlooms. While handlooms are there all over the country, pashmina handloom is available only in Kashmir. If we give encouragement to that, we can export it and earn a lot of foreign exchange.

Finally, I welcome and support the resolution on the 20-Point Programme and thank you, Sir, for giving me this opportunity.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : चेयरमैन साहब मैं बहुत मुख्तसर-सी अर्ज करना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने जो 20 प्वाइन्ट इकनामिक प्रोग्राम दिया है वह एक नई रोशनी है और एक रिवोल्यूशनरी स्टैप है। हमने देखा है कि इसमें काम हुआ है।

श्री विभूति मिश्र : जो रेज्योलूशन लाये हैं मैं उसके आपरेटिव पार्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हू कि अब प्लानिंग में जो भी रुपया दिया जाये वह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इडस्ट्री फ्यूल और पावर पर खर्च किया जाये ताकि हमारी इकानामी ज्यादा जैनरेट करे। नानएसैंशियल प्रायर्टीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नही है।

बाडेड लेकर खत्म हो गया है रुरल इन-डैटेडनैस को भी खत्म कर दिया गया है लेकिन सरकार जितना ज्यादा ररल बैंक्स को चालू करेगी उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा बढेगी। स्माल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलैस कल्टीवेटर अपनी तमाम पैदावार को मार्केट मे उस आदमी की निस्बत जल्दी लाता है जिसमे होड़ करने की कैपेसिटी होती है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आदमी इन-डैटेडनैस से निकल रहा है कही वह फिर न फस जाये।

अरबन प्रापर्टी की सीलिग के बारे मे इस वक्त सिर्फ यही कहना चाहता हू कि इस कानून से बच निकलने के और भी रास्ते बना दिये गये हैं, जैसे कि लैंड सीलिग के बारे मे बनाये गये थे। लैंड सीलिग के बारे में बडा डिसक्रिमिनेशन हो रहा है। एक के लिए 18 एकड रखा गया है और दूसरे के लिए 2,000 एकड रखा गया है। 20 एकड वाले के दो एकड काटे जा रहे हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि नीचे के लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन का इन्तजाम किया जाये। जब तक नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन के, जो प्रो-लैंडलार्ड और प्रो-इडस्ट्रियलिस्ट हैं पर नही काटे जायेंगे, तब तक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है ? जो लोग इस का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते है, जिन का इस मे इनवाल्वमेंट है, चाहे वे सी०पी०आई० के हो, या किसी और पार्टी के, जो यह चाहते हैं कि क्विक्कल वैरिफिकेशन कर के फालतू जमीन को लिया जाये और उस को तकसीम किया जाये, जब तक यह काम उन को नहीं सौंपा जायेगा, तब तक यह काम नहीं हो सकेगा।

सरकार ने होर्डर्ज से 1600 करोड रुपया निकाला है, इस की जितनी तारीफ की जाये, वह कम है। लेकिन जो अरबो खरबो रुपये का गोल्ड पडा है, उस को निकालने का इन्तजाम भी करना चाहिए। शादी वगैरह के लिए एक दो तोले सोना दिया जा सकता है, लेकिन बाकी का सोना निकालना चाहिए। क्या यह गोल्ड आस्टेन्टेशन, नुमायश, के लिए रखा हुआ है इस नुमायश को बन्द करना चाहिए और इस गोल्ड मे इकानोमी को आगे बढाना चाहिए।

स्विटजरलैंड और दूसरे मुल्को मे लोगो का जो लाखो करोड रुपया पडा हुआ है, सरकार को उस के बारे मे कुछ इन्तजाम करना चाहिए। सरकार को इस बात का इल्म है। जितना रुपया वहा पडा है और जितना वहा भेजा जा रहा है उस को निकालना चाहिए। दूसरे मुल्को मे रहने वाले हिन्दुस्तानियो को करोडो रुपये के डालर और पाउड यहा आ सकते है और हमारी फोरन एक्सचेंज की पोजीशन स्ट्रेंथन हो सकती है। क्यो नही नान-रेजिडेंट्स को फोरेन एक्सचेंज के अपने एकाउट्स यहा खोलने की इजाजत दी जाती है ? कोई ऐसा बैंक नही है, जो उन का एकाउट खोलने के लिए तैयार हो। इस बारे मे आर्डर्ज हैं, लेकिन सब एक दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योकि वे यह नही चाहते कि यह काम आगे बढे, शायद इस से उन का जाती नुक्सान होता हो।

हम ने प्राईवेट सक्टर को पब्लिक सैक्टर के मुकाबले मे दस बारह गुना ज्यादा रुपया

दिया है। कहा जाता है कि पब्लिक सैक्टर नुकसान में है। अगर पब्लिक सैक्टर मजबूत होगा, तो लोगो को ज्यादा वेतन मिलेगा और मुल्क को हर लिहाज से फायदा होगा। इस लिए उस को मजबूत करना चाहिए।

इस रेजोल्यूशन का आपेरेटिव पार्ट यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कामो को पूरा करने की जरूरत है। मैं खुले तौर पर कहता हू कि जब तक सरकार कांस्टीट्यूशन मे तब्दीलिया नही लानी है, तब तक कुछ नही होने वाला है। सवाल यह है कि जो मजदूर और दूसरे गरीब लोग आज देहात और कस्बात मे बेचारगी की हालत मे पडे हुए हैं, क्या उन की हालत को सुधारने के लिए सरकार लेजिस्लेशन लाना चाहती है या नही। हमारे ऊपर की सतह के लोग, जो इन्साफ देने वाले है, उन लोगो के बारे मे नही सोचते हैं, वे बडे लोगो के बारे मे सोचते है। इसलिए नीचे की सतह पर सोचना होगा। उस के लिए ऐसी लेजिस्लेशन तब लायी जा सकती है जब पहले कास्टीट्यूशन मे कुछ हद् तक तब्दीली लायी जाय और यह उन के लिए लायी जाय जो हैव-नाट्स हैं। हैव्ज के लिए बहुत हो चुका है, अब हैव-नाट्स के लिए भी कुछ आना चाहिए। और यह कास्टीट्यूशन कोई ऐसी रिजिड चीज नही है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सब से बडे जस्टिस थे गजेन्द्र गडकर उन्होने कहा है कि टाइम के साथ साथ हमारे कास्टीट्यूशन को पढने वाले और उस को शेप देने वाले जो लोग है उन को भी दिमागी तौर पर अपने अदर तब्दीली लानी चाहिए। क्योंकि हम फ्यूडिलिज्म से निकल कर आजादी मे आए हैं, इसलिए आजादी के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उन के मुताबिक हम को अपने सोचने समझने के तरीके मे तब्दीली लानी चाहिए।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** (मधेपुरा) सभापति महोदय, मैं आप को धन्यावाद देना चाहता हूं कि आप ने थोडा समय मुझे भी दिया। मैं श्री विभूति मिश्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू। इस से पहले कि मैं बीस सूत्री कार्यक्रम पर कुछ बातें करू, मैं कहना चाहूगा कि 25 जून से पहले जो देश की हालत थी और 25 जून को जब एमर्जेंसी का एलान हुआ, उस के बाद देश की जो हालत है इस को मद्दे नजर रखते हुए यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है जो प्रधान मत्री का क्रान्तिकारी कार्यक्रम है उस को रूबरू देखेंगे तो पता चलेगा कि इस की क्या अहमियत है। मैं देश के उस भाग मे आता हू जहा 25 जून से पहले अस्तव्यस्तता की हालत थी, हर जगह अराजकता फैली हुई थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव नही कर सकते थे, कही कुछ प्रोडक्शन नही हो रहा था, इंडिसिप्लिन का आलम था। 25 जून को एमर्जेंसी आने के बाद देश का आलम कुछ बदला, सारे लोगो मे एक डिसिप्लिन आई, सेस आफ रेस्पासिबिलिटी आई, लोगो ने समझा कि देश के लिए हमे कुछ करना चाहिए। उस के इम्मीडिएटली बाद आप ने देखा 1 जुलाई को प्रधान मत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम का एलान किया। उस के बारे मे मैं ज्यादा कुछ कहना नही चाहता हू।

मैं केवल एक आस्पेक्ट के बारे मे कहना चाहता हू। आप जानते हैं कि यह देश गरीबो का देश है। 80 प्रतिशत लोग देहातो मे रहते हैं और जमीन पर या जमीन के आसरे जीते है। उसी के माध्यम से उन की रोजी रोटी चलती है। तो असल बात यह थी कि किस तरह से यह जमीन जो चन्द लोगो के हाथ मे आई थी, वह आम लोगो के हाथो मे पहुचे। उस के लिए लैंड सीलिंग हर जगह हुई और जहा जहा जिस तरह की हालत थी उस के मुताबिक वहा वह लागू हुई। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हू जैसा कि मिश्रा जी के रेजोल्यूशन मे भी है कि वास्तव मे कहा उस पर अमल

[ श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ]

नहीं हो रहा है, यह देखा जाय। लैंड सीलिंग मे आप को जानकारी होगी कि बहुत से लोग तो अपने नाम से नही बल्कि कुत्ते बिल्लियो के नाम से जमीन का ट्रांजेक्शन किए हुए है। बहुत बडा लीगल फ्राड है, आप पता नही लगा सकते कि जमीन उन के नाम है या क्या स्थिति है। किस के नाम वह जमीन वास्तव मे है यह मालूम करना कठिन है। लेकिन मैं आप से यह कहना चाहता हू कि हमारी जो मौजूदा बिहार सरकार है वह काफी अच्छा काम इस दिशा मे कर रही है। जैसा मधुकर जी ने बताया काग्रेस के ही लोग ऐसे है जिन मे एक के पास 4 हजार बीघे जमीन थी और अभी आप ने देखा कि उन को निकाला गया है, दिनेश सिह जो एक्स मिनिस्टर भी हमारे यहा रह हैं। तो यह नही कहा जा सकता कि उस दिशा मे कुछ नहो हो रहा है।

जब से हमारे नौजवान मुख्य मत्री जगन्नाथ मिश्रा जी आए है उसके बाद मे इस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उन के मुख्य मत्रित्व काल मे बहुत सारे काम हुए। हरिजनो, शड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासेज के लिए जितनी बडी बडी पोस्ट्स हैं चाहे वह नामिनेशन की पोस्ट्स हो या और तरह की, चाहे वह यूनिवर्सिटीज के वाइस चासलर की पोस्ट हो या सर्विस कमिशन के मेम्बर की पोस्ट हो, या यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के मेम्बर की पोस्ट हो, ऐसी जितनी बडी बडी पोस्ट्स है जिन पर सरकार के नुमाइन्दे जा सकते है उन पर उन को तरहीज दी गई है।

16.59 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

एक बात और मैं कहना चाहता हू कि मोर्गेज की हुई जो भूमि थी (व्यवधान) उसके बारे मे

हमारे बिहार मे एक लेजिस्लेशन हुआ है कि यदि सात वर्ष तक किसी की जमीन किसी के पास मार्गेज रही हो, इस्ट्रक्ट के रुप मे वह उस जमीन से फसल उपजाकर खा रहा है तो उसके बाद वह कर्जा माफ माना जायेगा। मैं चाहता हूं इस तरह का लेजिस्लेशन देश के अन्य भागों म भी आना चाहिये।

हमारे बिहार के स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटियों मे खानेपीने और अन्य आवश्यक वस्तुओ का कोटा दिया गया है और वहा पर बुक बैंक्स की व्यवस्था भी की गई है।

अन्त मे मैं एक बात और कहना चाहता हु कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका इम्पलीमैन- टेशन करने वाले वही अफसर लोग है जिनका दिल दिमाग बदला नही है और न ही वह बदलना चाहते है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं इन अफसरो के लिए भी कोई ओरिएन्टेशन कार्स और ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये ताकि उनका भी दिल दिमाग बदल सके और आज के इस बदले हुए समय मे वह भी समझे कि उनकी भी कुछ जवाबदेही है। यद्यपि हमने इम्प्लीमैन्टेशन कोटीज बनाई है ब्लाक, जिला स्तरो पर लेकिन वास्तव मे काम करने वाले तो अफसर ही होगे। दूसरे लोग अपने सुझाव अवश्य देगे लेकिन सारा काम तो उन्हे ही करना है। इसलिये उनके लिए भी कोई ओरिएन्टेशन कोर्स और ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये।

जहां तक ग्राम मजदूरी की जहा तक बात है, इसके सम्बन्ध में बहुत से कंट्राडिक्शन्स और कन्फ्यूजन हैं। बाई एड लार्ज हमारे जिले मे तथा अन्य जिलो में यह प्रथा नहो है, यदि हमारे अन्य दोस्तों को अन्य जगहो पर इसकी जानकारी है वे यदि सरकार के सामने इसको लायेगे तो उसपर अवश्य कदम उठाया जायेगा तथा उसको दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

आपने रूरल बैंक्स की व्यवस्था

बैंक्स की व्यवस्था की है और कहा है रूरल डेटस को आप समाप्त कर देंगे। आज देहात में किसानों को खेती के लिए और शादी वगैरह के लिए, हर काम के लिए कर्ज चाहिए लेकिन महाजन उनकों कर्जा देना नहीं चाहते है। यदि आप उनके लिए बैंक्स की सुविधा नहीं देंगे, यदि आप उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंचेंगे तो वह परेशानी में पड़ जायेंगे आखिर में मजबूर और लाचार होकर उनको महाजन के पास जाना पडता है और अब वह लोग पहले से प्रचंलित सूद से भी ज्यादा सूद पर कर्जा देते हैं। इसलिए देहातों में इस अवस्था को दूर करने का उपाय करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हू।

MR. CHAIRMAN: Shri P. M. Mehta: only 5 minutes.

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): I will try.

MR. CHAIRMAN: Let me tell you that we have to conclude this today. The hon Minister has said that he would like to have about 40 to 45 minutes. That means, we must finish the debate by at least 5 15 P.M. There is the right of reply also. Then, there is the next Resolution in the name of Shri Unnikrishnan. That is also to be taken up. You must cooperate Otherwise, how can I do it?

SHRI P. M. MEHTA: I will be as brief as possible.

Mr. Chairman, Sir it would not be out of place if I mention that this 20-point economic programme was announced in the wake of Emergency. I may give a little background that before the announcement of the 20-point economic programme the economy was deteriorating and it had created a very adverse impact on the weaker sections of the society.

I must compliment the hon. Member, Shri Bibhuti Mishra. He is a seasoned politician and he has very timely brought this resolution for discussion in the House; because, you know very well that there was a time-bound programme, there was a 13 point programme and several other programmes but, as he has rightly pointed out there was either non-implementation or desultory implementation of these programmes.



Now the time has come when we should evaluate the total impact of this 20 point programme. It is not reflected in the general economy at present—as, for example, in agricultural economy. Now, what has happened is that the price of agricultural production has declined but, at the same time, the prices of inputs like improved seeds fertilizers, pesticides, crude oil and other necessary inputs have not comparatively declined but, in some cases, have even gone up. Therefore, this has resulted in non-economic agricultural operations. The tillers are losing today; they are not getting a remunerative price. By this I don't mean to say that the prices shall be raised, but the farmers should be given the facility of concessional prices so that they can have a remunerative price. So, agricultural economy has deteriorated and has not improved.

The same is the case with industrial economy. Today, as far as textile mills are concerned, day to day mills are being closed down. Jute mills are in the same condition. There is recession in automobile industry also and in rubber industry and engineering industry also. Thousands of workers have been laid off and the industrial economy today is not in good shape. So, this is my second point, that the impact of this programme today has not been reflected in the general economy either in agriculture or in industry.

Now, I would like to make one or two suggestions regarding this 20 point

[Shri P. M. Mehta]

programme. Take the example of distribution of land to the landless labourers. In Gujarat this land-reform programme was over long ago and we are distributing land and giving some other facilities also to the landless labourers. So, I want to suggest that, for this point and other points also, there must be a package deal for all the points, including distribution of land to the landless labourers. At the same time, you must plan to give them equipment and financial assistance. You must supply them with small tractors etc. on hire and give them financial assistance also so that he can till the land and it will not remain uncultivated.

So also with electricity. You must chalk out a programme. When you are developing backward areas, you must give priority to giving energy and power to these areas. Today what is happening? Even where the fields are electrified and the pumps are working, they are not getting enough power of energy for their own irrigation. Therefore, for the new programme all these details should be worked out, and the package deal for each point should be worked out and implemented, so that it can bring about some results.

Now, what is going on? Let us examine the political aspect also. With regret I say that, instead of laying emphasis on the implementation and labouring hard for that in the rural areas, what they are doing is that they are only raising a chorus praising the 20-Point Programme; sometimes, it is reduced to a flattery. If that is not stopped, I assure you this Programme is bound to fail. This Programme is not meant for flattery or praising, but for actual implementation.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): We are doing that.

SHRI P. M. MEHTA: Certainly not.

The Mover of the Resolution has rightly pointed out:

> "This House, while expressing its deep appreciation of the 20-point Programme initiated by Government, notes that its implementation at the State, district, block and village level has not been quite satisfactory so far and, therefore, recommends that necessary steps may be taken by Government immediatly to remove all legal and administrative hurdles in the implementation of the Programme."

What are the legal lacunae? These should also be included in the package deal.

Lastly I may say that, in the State of Gujarat we are implementing not only the 20-point Programme but more progressive programmes; the Government of Gujarat is implementing this 20-point Programme plus various other programmes; we have the 62-point Programme and we are implementing it. Therefore I can say that we are one of those who are already implementing this Programme.

ramme.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: (निजामाबाद) : सभापति जी, यह इमरजेंसी का ऐलान कुछ भी नहीं होना, उस का मतलब कुछ भी नहीं होना अगर यह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम नहीं होता। इस से पहले किसान बैंक के पीछे फिरता था, लेकिन आज बैंक वाले किसान के साथ फिर रहे हैं। एक जमाना था जब किसान पानी के वास्ते नदी को जाता था, आज नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच रहा है। हर आदमी मेहनत से काम कर रहा है। मेहनत करना लोगों की आदत होती जा रही है। जो हड़ताल पैदा करने वाले थे वह लोग थोड़े दिनों के लिये अपने देश से गैरहाजिर हैं।

अगर हर्डल्स छोड कर वह मेन स्ट्रीम मे शामिल हो जाते तो देश का कल्याण होता।

हमारे आन्ध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, श्री वेन्गल राव ने पार्लियामेट और असेम्बली मेम्बर्स की एक कमेटी बनायी है जो 20 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की देखभाल करेगी। यहा आ कर यह कहना कि स्टेट मे काम नही हो रहा है तो मे उस एम० पी० महोदय से पूछता चाहता हू कि वहा के चीफ मिनिस्टर को क्या उन्होने यह बात बतायी ? अगर उन्होने कुछ ऐक्शन नही लिया तो प्राइम मिनिस्टर को इन्फोर्म किया ? अब पार्लियामेट मे कहना कि कुछ भी स्टेट मे नही हो रहा है, बिल्कुल गलत है। हमारे चीफ मिनिस्टर, श्री वेन्गल राव ने सरकारी जमीन का पूरा का पूरा बटवारा किया है दिसम्बर 1975 तक/सीलिंग मे ज्यादा जो जमीन निकलने वाली है उन के बटवारे का इन्तजाम भी जून, 1976 तक खत्म हो जायेगा।

**श्री मुहम्मद जमीरुर्रहमान** (किशनगज) : रेज्यूलूशन का जो आपरेटिव पोशन है, वह यह है

That necessary steps should be taken by the Government to remove all legal and administrative hurdles in the implementation of the programme

मैं अर्ज करना चाहता हू कि जब तक आप कास्टीट्यूशन को एमेंड नही करेंगे उस वक्त तक इस प्रोग्राम का इम्पलीमेंटेशन होना मुश्किल होगा। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करने मे आती है उन को दूर करने के लिए आप को कास्टीट्यूशन को एमेंड करना होगा वैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोशिश कर रहे है कि यह काम हो।

दूसरी बात यह है कि इस मे जो 20 सूत्री कार्यक्रम का लास्ट बट वन आइटम वीकर सेक्शन की मदद करने के बारे मे है, उस के बारे मे मैं यह कहूगा कि इस मे मुस्लिम माइनोरिटी कम्युनिटीज का इन्वाल्वमेंट हो, हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज का इन्वाल्वमेंट हो और आदिवासियो का इन्वाल्वमेंट हो। बिहार स्टेट मे इस छोटे से पीरियड मे काफी काम हुआ है। वहा पर गरीबो मे जमीने बाटी गई है, मकान बनाने के लिये जमीन के पट्टे दिय गय है और ला एण्ड आर्डर की सिच्युऐशन को ठीक किया गया है।

आखिर मे मैं यह गुजारिश करूगा कि सरकार को इस बात का निश्चय करना चाहिए कि इस प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करने के लिए कास्टीट्यूशन को तुरन्त बदलना चाहिए जिस से कि वह अवाम का कास्टीट्यूशन हो सके और लोगो की सही खिदमत हो सके।

[شری محمد جمیل الرحمان

(کشن گنج) : رزیولوشن کا جو آپریٹو پورشن ہے وہ یہ ہے :—

"That necessary steps should be taken by the Government to remove all legal and administrative hurdles in the implementation of the programme

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کانسٹی ٹیوشن کو امینڈ نہیں کریںگے اسوقت تک اس پروگرام کا امپلیمینٹیشن ہونا مشکل ہوگا - لیگل اور ایڈ منسٹریٹر ہرڈلز جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پر پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے آپ کو کانسٹی ٹیوشن کو امینڈ کرنا ہوگا - ویسے ہم ڈسٹرکٹ لیول پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام ہو-

دوسری بات یہ ہے کہ اس میں

[شری محمد جمیل الرحمان]

جو ۲۰ سوتری کاریہ کرم کا لاسٹ بٹ ون آئٹم ویکر سیکشن کی مدد کرنے کے بارے میں ہے -

اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں مسلم مائنورٹی کمیونٹی کا انوالومینٹ ہو، ہریجن اور بیکورڈ کلاسز کا انوالومینٹ ہو اور آدی باسیوں کا انوالومینٹ ہو - بہار سٹیٹ میں اس چھوٹے سے پیریڈ میں کافی کام ہوا ہے - وہاں پر غریبوں میں زمینیں بانٹی گئی ہیں- مکان بنانے کے لئے زمین کے پٹے دئے گئے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کیا گیا ہے -

آخر میں میں یہ خواہش کروں گا کہ سرکار کو اس بات کا نشچے کرنا چاہئے کہ اس پروگرام کو امپلیمینٹ کرنے کے لئے کانسٹی ٹیوشن کو ترنت بدلنا چاہئے - جس سے کہ عوام کا دستی ٹیوشن ہو سکے اور لوگوں کی صحیح خدمت ہو سکے -

**श्री टी० बी० कांबले** (लातूर) सभापति जी, जो प्रस्ताव मिश्र जी ने रखा है, उस का मैं समर्थन करता हूं और उस सम्बन्ध मे कुछ थोडे से सुझाव देना चाहता हू।

20 सूत्री कार्यक्रम को अगर सही ढग से अमल मे लाया गया तो जितने वीकर सक्शन हैं उन को ही लाभ होने वाला है खास तौर से भूमिहीनो को जमीन देते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि उन को इतनी जमीन दी जाए ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ढाई एकड या तीन एकड जमीन से वह कुछ नही कर सकने और इस का नतीजा यह होगा कि जो बडे जमीदार हैं वह उन के हाथ मे चली जाएगी और उन से वह उस जमीन पर काश्त करवाएगे। इसलिए इतनी जमीन उन को देनी चाहिए कि उन का गुजर-बसर हो सके।

दूसरी बात मैं घर बनाने के सम्बन्ध मे कहना चाहता हू। घर कुछ बनाए जा रहे है लेकिन कई जगह कमजोर घर बनाए जा रहे है और ऐसे घर बनाने से कोई ज्यादा फायदा उन को नही होगा। घर बनाने मे जो मटिरियल लगता है, जो सामान लगता है वह अच्छे किस्म का उन को दे दिया जाए ताकि अच्छे घर वे बना सके और कम मे कम चार पाच साल तक रह सके। बाद मे बैंको स ऋण ले कर या दूसरी सहायता ले कर वे अपने घर बना सके तो अच्छा होगा।

तीसरी चीज बेरोजगारी के सम्बन्ध मे कहना चाहता हू। बेरोजगारी बढती जा रही है। इसके लिए उपाय यह है कि देहातो मे ज्यादा से ज्यादा कारखाने आप खोले ताकि देहातो से शहरो की ओर लोग रोजगार के लिए न दौडे। अक्सर कारखाने शहरो की तरफ खोले जाते है। इससे शहरो की आबादी बढती जाती है और बेरोजगारी का हल गाव मे नही निकलता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा कारखाने देहातो मे खोले ताकि वहा के लोगो को रोजगार मिल सके।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ही घर के लोगो को एक से ज्यादा नौकरी न दी जाए और एक घर मे एक

आदमी को ही नौकरी मिले तो अच्छा होगा। इससे दूसरे लोगों को चान्स मिल सकता है। अब तो यह होता है कि एक घर में से तीन तीन और चार चार लोगों को नौकरी मिल जाती है, जिस से दूसरे लोगों को एक घर में एक को नौकरी नहीं मिल पाती।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाओ। उत्पादन बढ़ना जरूरी है लेकिन उस की कीमत न घटे, यह भी देखना चाहिए। इस के अलावा यह भी देखना चाहिए कि किसानों को जो चीजें मिलती है जैसे कि कैरोसियन आयल है और खाद इत्यादि चीजें है, वे इतनी महंगी हो गई है कि किसान को खरीदना मुश्किल हो जाता है और किसान जो अपनी चीजों का उत्पादन करता है उस को कम भाव मे देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि उस की चीजों की कीमतों का एक लेबिल कर दीजिए ताकि कीमत का सतुलन रहे। उस के साथ ही जो चीजें उस को खरीदनी पड़ती है जैसे कि तेल है, खाद है और दूसरी चीजें है, उन के दाम भी फिक्स कर दीजिए ताकि किसान को सुविधा हो सके और किसान को ज्यादा पैदावार करने मे हिचकिचाहट न हो। किसान का इस बात की गारण्टी होनी चाहिए कि जो माल वह पैदा करता है, उसका दाम उस को सही मिलेगा। जब ऐसा होगा, तभी वह उत्पादन ज्यादा बढ़ा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हू।

MR. CHAIRMAN: The time fixed for this Resolution is, in fact, over. If it is the sense of the House that the time should be extended, both the hon. Minister and the mover of the Resolution will get some time. I think, we can extend it by 40 minutes.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (नवादा): मैं प्रस्ताव करता हू:

"कि इस सकल्प के लिए निर्धारित समय को 40 मिनट और बढ़ाया जाए"।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the time allotted for this Resolution be extended by another forty minutes."

*The motion was adopted.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI I. K. GUJRAL): I am grateful to you for giving me an opportunity to intervene in this very worthwhile debate both now and two weeks ago.

I have noticed a great deal of enthusiasm on the part of the hon. Members to participate in this debate and I think you will agree and the House will agree that in the context of this discussion, we have achieved a great deal. I particularly wish to thank my senior colleague and friend, Shri Bibhuti Mishra who was responsible for giving us this opportunity for discussing this programme.

The programme announced by the Prime Minister, I feel, has given this, a new orientation and I mention it because it constitute an action programme intended not only to galvanize the causes of growth but also to effectively involve the working classes and the community as a whole in the mainstream of development.

The programme has in fact set in motion the thinking and its translation into practice needs a re-orientation in our approach to various problems.

I think in this House, particularly in the Parliament, we have reason to be very grateful to the vision of the great leader of our country, Pandit Nehru, whose vision gave us the

[Shri I. K. Gujral]

planning process of this country and thinks to the *planning* process, whatever we have achieved in this country in the last 25—30 years is primarily due to his vision. His vision gave us the approach and orientation and with the planning process, the country has improved and grown to its present stature. I will not take the time in trying to give you the figures as to how the country has developed because all the learned members here know better than I do how proud we can be of our achievements. But I will try to draw your attention to one aspect of our life and that is agriculture.

Rightly one of my very learned friends mentioned that this is a country whose population primarily depends on agriculture and our production process and our economy also basically depend on what is the shape and phase of agriculture in this country Sometimes we have been made to believe, thanks to the propaganda of those who do not have faith in this country's economy and in what it has achieved, that in agriculture we have stagnated and we have not grown. Sometimes, it is good because it reminds us of the good thing.

Let us remind ourselves of the fact that during the period itself, we have more than doubled the production of foodgrains. When the Plan started if I remember correctly, our production used to be of the order of 52 million tonnes. To-day, we are thinking in terms of 110, 112 or 114 million tonnes. It is not a mean achievement because it basically means that the country's rate of growth in agricultural production has been of the order of 2·67 per cent compound rate of growth.

This is something which has not been achieved by many countries, not only in the developing world but also in the developed world. We are hoping that at the end of the Fifth Plan—and that is our target—we should be in a position to produce 140 million tonnes of foodgrains. If we talk in terms of the rate of growth which can take us to 140 million tonnes, it obviously means that we must have a fresh look into the main inputs, inputs both in the sense of what we commonly call, agricultural inputs like fertilisers and water but also we must think in terms of human inputs. We do realise and appreciate, I hope, that unless we realise the major human productive force, till then, a major change in our agricultural scene will not come and I think that is why there is a great deal of emphasis in the Twenty Point Programme on the man—land relationship, we have got to keep in mind a fact that apart from this aspect of human injustice which is basically involved, if we are really keen that production in agriculture should grow and increase, then it is very important that for us to realise and appreciate that, ultimately it is the man who produces the goods, it is the man who produces cereals, it is the man who produces cotton and other agricultural produce and unless the man who is working on the soil knows that what he produces will go to him ultimately and the result of his sweat and labour is not going to be taken away by somebody-else, till then he is not able to put-forth the very best in him Therefore, I think this is the basic approach of the twenty-point programme that we must look at those factors in detail which have arrested these human factors which contribute to growth and which contribute towards the picking up of agriculture I am not saying anything profound or anything very unusual when I say this thing that both the yoke of the tradition and the cruelty of history has now to be undone. Unless we are in a position to do this, we should forget our targets. No amount of fertilisers and no amount of input in irrigation will achieve results. Sometimes, in innocence, we are made to believe only as if land, farms, tractors, fertilisers, good seeds get us results. To an extent they

do. But ultimately and basically, it is the human-factor which matters. Again, I may repeat,—it is relationship with land which matters.

Our history, unforunately has given a raw deal to many of our fellow citizens. One of the raw deals by the British to our farming community was in the heartland of India what? is called 'permanent settlement'. What dose permanent settlement mean? Permanent settlement basically means nothing else except that both land and man were given on lease to somebody so that they become perpetual slaves. This played havoc with us. It played havoc with our society socially. It played havoc with our production and productivity. It played havoc with man's vision, man's existence.

Now, we realise another aspect of it. Since permanent settlement came in the country, all the records were not available. We are not able to decide to-day, who owned which land and when? How was the land taken away? Even the land revenue records were not available. Therefore, when we talk in terms of land reforms, we have to lay a great deal of emphasis on completion of those records That is why both as a part of the twenty-point programme and as a part of the planning process, we are laying a great deal of emphasis on completion of these records. In this year's plan, in the next year's plan, in the last year's plan, we are allocating adequate funds to the States so that they quickly complete the records Because, once the records are complete, land distribution will become rational, just, correct and as it should be. I think that is the essence and the fundamental on which we can proceed. Only then it is possible for us to distribute land adequately.

The second step, of course, is that not only the land records must be completed, but we must get rid of the evil of crop sharing as soon we possibly can. In a way, it is a part of the same thing about which we were talking just now. Crop sharing ultimately means that the man who labours gives away half or more than a half to the man who has no other entitlement except that at one time in history he was able to usurp his or their right. To-day they own 4,000 acres or 40 acres and they remain absent from the land. They think they have a right to take away the share of the crop, simply because at one stage in history they were stronger than those who were deprived. Crop sharing must end not only as a part of social injustice but as an essential ingredient for more production. Unless the man who produces knows that all that he will harvest will go to him for his own children and his family, you cannot expect the best out of him. That is why the earlier we get rid of it, the better.

I do not want to talk about land ceiling to-day. Very fortunately, in India, the national consensus has now emerged about land ceiling. I think that phase is over—how many acres should be the ceiling, what is economic unit, etc, etc. So, I will not take your time on that. Since national consensus exists on that, we have to now give a visible push to see to it that land is distributed. Fortunately, since the twenty-point programme implementation started and also last year some visible results have been achieved, some of my friends have complained that the implementation is not as good as it should be. Perhaps, they are right. Perhaps, it does need more push. Perhaps, it does need more looking after. Perhaps, it needs more supervision on the part of those who are in political life, because, ultimately, we must remember one thing—no social change is ever brought by any bureaucracy anywhere. Let us remember the fact that the bringing in and ushering in of the new change and social transformation is our responsibility. We have been held responsible by our

[Shri I. K. Gujral]

people and we have been given this charge to bring a social change. As persons following the legacy of Gandhiji and Nehru we must keep in mind the fact that any social revolution which has to come in the country has to be ushered in by those who have taken the pledge to stand by the people and I hope that we, whether sitting on this side of the House or on that side of the House, having the totality of public life in the country, believes and I hope, rightly, that we must usher in that change. For the last 20 or 25 years, if the results were limited they were basically because of the fact that we thought that revolution could be command performance. Social revolution can never be command performance. Social revolutions are always ushered in by those who have participated in the social revolution itself irrespective of their own interests. And that is why even when the results achieved are limited it will serve no purpose if we stand in this House and only keep on criticising the bureaucracy. It is not bureaucracy's rule, which we must all realise. I agree with a friend of mine who just now said that it is ultimately a social movement, a political movement, a movement which we must all need, which will bring in results And that is why, whether we talk in terms of land reform or we talk in terms of social transformation, basically, it is very important for us to realise and appreciate that nobody else can play our role. And we cannot bring in revolution by proxy. Revolutions have to be brought in by offering our own sweat, our own labour, our own effort, our own blood, if need be and that is why it is essential that we must participate in this endeavour.

Now, having said this, I may say that results are being achieved even then and the figures given to me show that till about the middle of December, the total acreage taken possession of in various States was of the order of about 3,04,300. The land distributed was of the order of 1,13,429 acres. The results are worthwhile mentioning. When we take the claims which have now been filed, both on voluntary basis and on official initiative, the same is quite substantial. The figures with me show that till the end of December approximately 8,81,713 returns have been filed voluntarily and 2,21,049 have been filed on official initiative and the total area declared surplus was of the order of 6,09,659 acres. This is the total of all the States about which I have the figures. But I am sure this figure will mount up because these are not the totally comprehensive figures.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): This is ceiling land which is coming under ceiling. You are giving such a figure. They are Government lands which have been distributed.

SHRI I. K. GUJRAL: I am talking of land reforms. I am talking of those lands for which returns have been filed and talking of those lands which have been partly distributed. But I am told, the progress of distribution will catch up considerably from now onwards and I hope by the time we meet next time in the House, perhaps I will be in a position to give more worthwhile figures.

I hope the House will agree with me that mere distribution alone does not solve the problem. Land can be distributed, it should be distributed, but we are primarily giving land to those who have been deprived for ages. And deprivation has many facets and we rightly call it poverty also. Poverty also means that the man who has been given land does not know what to do with it, he does not even have a pair of bullocks. He does not know how to buy fertilizers because he does not have the money. He cannot get water. He cannot sink a tube-well. He cannot get electricity, he does not have the money. So, when we think in terms of doing a

new social justice, and if I may use the word, 'new social deal', it is very important for us to remember that we think in terms of total package deal. A man should not get only land, but he must have adequate means to get these problems also solved.

And that is why we are thinking in terms of having a new rural credit policy. New rural credit policy means cooperative credit. It also means new social credits availability. And that is why it must catch up. Again, more important than making the institutional credit available is the political vigilance and unless the political vigilance is available, the deprived which is uneducated, the deprived who has never learnt to get his dues will never be able to get it and, unless at the social and local village level, people are available to look after his interests, he will never be able to get it. Therefore, I feel that some beginnings have been made—some negative, some positive. I mentioned the positive also. I would also like to mention the negative. The negative is the 20 point programme. It talks, for instance, of wiping off the debts. But, what is the debt after all? The debt in rural life for the poor man is not the money that he took but, it is, by and large, the overcharged interest; it is by and large the price that he pays by his ignorance; it is by and large the price that he pays because he is unable to defend himself; it is by and large a phase of social inequality. Add that is why when we talk in terms of wiping off of his debts, I think, in a way, we are also trying to let him stand up and, after centuries, demand his own right.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Can you not ban the private lending?

SHRI I. K. GUJRAL: Banning is not difficult. The amount is subsidised by the social institution. Now, social institutions cannot be wished overnight. Social institutions have to be built in gradually. And that is where the work at the local level will have to be done. Even in the centre and the State capitals if we decide that the social institutions for credits will be available, they will not work effectively then unless you and I and the colleagues sitting here roll up our sleeves and say that we will stand up in the village and see to it that the man gets his dues, the money-lender, whether he is there or not, will not be able to exploit the man. Whether you abolish it or not, there is always a way of doing it. Only if the social need and the social availability are married together, the private interest comes in. But, if we do not allow this unhealthy marriage to be formed, then it is very very significant for us to realise that this institution will end. In the same context and in the same breath, I would also like to mention about bonded labour. Bonded labour, we all know should end. We realised to our shame after 30 years of freedom and we woke up and thought that some of our fellow citizens were still in the bonded labour which is another respectable name—not respectable, there is another name —for human slavery. I do not know how long we tolerated it and why. I am glad that this twenty-point programme has focussed on this. Legislations have been passed. But, legislations along cannot solve the problem. At the grassroots, we have to see that each Indian, wherever he may be—whether he is an Adivasi or Harijan and whether he is a landless labourer or anyone and in whatever name of culture and of our tradition, he who is subject to work for others is released from there. That is what we must see to and that, I think, is one of the basic points of emphasis to the twenty-point programme.

Sir, I must also say that this entire packet of inputs will create a social environment and social problem of a different nature and to some of which I am drawing your attention. A hump in our production has now come. We have decided for ourselves, and, right-

[Shri I. K. Gujral]

ly so, in the Plan that by the end of the Fifth Plan, our foodgrains production should be 140 million tonnes. Now, we must work backwards—what will these 140 million tonnes give us and how much of fertiliser, how much of irrigation, what type of man and land relationship, how much of electricity, how many tube wells there should be. And that is where the Plan has tried to plug in the holes.

Some of my friends have drawn my attention in the debate to the problem of fertilisers. Fertiliser, unfortunately, has been one of our difficulties because it is, as you all know, by and large petroleum-based and with the new inflationary pressures that we were faced with the prices of fertiliser also went up. That is why the difficulty arose. Therefore, when we had to raise the price in 1974, it was primarily raised because we had to import a very expensive thing and, if we had not raised the price at that time, the element of subsidy in the budget would have been of the order of Rs. 400 crores.

Now there was no escape from it To an extent the prices were raised, but even after raising and revising the prices, the subsidy still continues and, fertilisers today, are subsidised to the extent of Rs. 140 crores. The national budget bears the brunt of it and that is where Rs. 140 crores have to be found. I must say although the subsidy is there the consumption of fertiliser has gone down and we have to see to it that the fertiliser consumption does not go down. In the same context I must mention that in food our food targets have to be considerably checked up. The progress is being sustained and the production is picking up but I hope we will be in a position to turn it into a permanent habit rather than a periodical happening and unless we are able to do so the problem will not be solved. Sir, I might also mention that the procurement about which doubts have been expressed is going on satisfactorily. In this kharif crop elaborate arrangements have been made for procurement and by the end of December 1975 about 70 lakh tonnes of kharif cereals has been procured as against 14 lakh tonnes in the same period last year. Therefore, if there is any doubt about procurement of foodgrains we must not get worried about. The targets will be kept. Sir, not only should we procure for our consumption but we must also move towards building up buffer-stock. It is an important back-rock and the bed-rock for building our economy so far as foodgrain is concerned. About rural indebtedness I might add that by the end of December along with these 50 rural banks each with 100 branches have been planned—five banks have been established in various places—and we are hoping along with the cooperative credit to a very large extent this problem will be solved.

Mr. Chairman, the 20-point programme has also emphasised to a large extent the minimum agricultural wage. Now, minimum agricultural wage has been fixed and I am told a review has been undertaken by the States and minimum wages have enhanced in most of the States The administrative arrangements for implementation of the minimum wages are being geared up in the States. This is what I am told but I also hear some friends saying that perhaps this is more on paper than on the ground Therefore, I might repeat, implementation supervision has to come on the political base and, I hope, when we go back to our constituencies when the session is over we will be able to come back and tell the concerned Ministers as to what we have seen in the field so that if more tightening up is needed to make it effective. it could be done.

Similarly I had mentioned about the bonded labour and the steps that had been taken. Now, I come to a very

significant aspect of the 20-point programme, namely, house-sites. I would like to say that progress has been satisfactory in this respect. This hon'ble House will recall, we have been talking about house-sites for a fairly long time not only because we feel that the people in the rural life should have houses but also because we feel that house-site is the first beginning of feeling of security on the part of the landless workers. It is the harijan, adivasi or landless worker who generally does not own a house-site and wherever the landlord gets upset with him in his anxiety to be unfair to him he would push him out not only from the land but also from the house-site. Therefore, this programme is being given a great deal of push and the progress in this context is satisfactory. I am given to understand that by the end of December about 60 lakh house-sites would have already been distributed but I share one observation made here that merely giving house-site does not solve the problem unless the man is able to put up a semblance of a house till then what is the use of giving the house-site. But the difficulty is that the house shortage in rural life is very large. The last survey, conducted some years ago, put the figure at 18 million.

MR. CHAIRMAN: Time is getting.

SHRI I. K. GUJRAL: I was to have 40 minutes

MR. CHAIRMAN: True. From 5.20 onwards 40 minutes brings it to 6 P.M. The idea was that unless we give five minutes, even two minutes, for the next Resolution to be moved, it will not survive. Therefore, I seek your co-operation

SHRI I. K. GUJRAL: The housing shortage in rural life is of the order of 18 million. To this, unfortunately, every year another 1.8 million is added. Therefore, the house shortage in rural life is increasing. This house shortage generally falls on the very poor. As you know, the latest survey gives us very devastating figures about the people below the poverty line. I will not take your time in giving these. But if we look at them, it is enough to upset us. But I am glad that in some States like Kerala and Orissa, some good work has been done in regard to rural houses also and I hope that as we are able to spare more funds for the plan we will be able to pick up in this direction.

I was emphasising, I hope rightly, that basically our economy is a rural economy, and that is why we have tried, when we talk in terms of inputs, to put the emphasis on irrigation The twenty-point programme talks about adding about 5 million hectares in the course of the Plan. By the end of 1976, 171 million hectares would be under the plough. Out of this, only 45.30 million hectares would be irrigated in the proper sense of the word. If we are talking generally in terms of the miracles of Punjab and Haryana, these miracles are basically miracles of irrigation. If we are able to do more irrigation, if we are able to add to our figure of 45 million hectares another 5 million, it will be a substantial push forward and then I hope our production will go up in a similar way. In 1974-75, we were able to invest Rs. 885 crores and add 0.65 million hectares. In the current year, we are investing Rs. 500 crores and adding 1.1 million hectares. Next year we intend to step this up to 1.10 million hectares. I am sure by the end of the Plan period, we will be able to add what we require, namely 5 million hectares.

In today's context, when I talk of irrigation, I cannot get away from energy. Energy is not only essential for industry but is also of equal importance for irrigation. That is why when we talk in terms of lift irrigation, when we talk in terms of pumping sets, it is very important that we

[Shri I. K. Gujral]

do a great deal of investment in the energy sector itself. Hence it has become a core sector. I will not take your time much on this. We are emphasising a great deal on pumping sets. In 1974-75, we were able to energise 1.66 lakh pumps. In 1975-76 (this year), we are wanting to add another 1.73 lakh pump sets.

Also we are investing a great deal of money, that is approximately Rs. 300 crores, in minor irrigation. This will ultimately take our progress a great deal forward. That is why the allocation for irrigation and power scheme during the current year has been increased by about Rs. 100 crores. Additional Central assistance of Rs. 85 crores has been made to States to accelerate the work of irrigation and power projects which are in an advanced stage of construction. This again will be able to solve, to a great extent, the problems that my friends have drawn our attention to.

In 1974-75, we were able to add 1.7 million kilowatts. In the current year, we will add 2.6 million kilowatts. We wish to continue this pace and also emphasise on electrified villages, the number of which has now reached approx. 1,70,000.

I know I am taking a lot of your time. I am trying to jump the twenty-point programme. It is a very comprehensive, wholesale programme...

AN HON. MEMBER: Why not extend the time?

MR. CHAIRMAN: Under the rules, it is not possible.

SHRI I. K. GUJRAL: Unless I give a full picture of the steps taken, it will not be possible to appreciate the progress made.

MR. CHAIRMAN: I know your difficulty.

SHRI I. K. GUJRAL: That is why I am handicapped. It is not only the members sitting here but the country would want to know how far we have implemented it.

So far I was talking about the rural sector. The main difficulty that we have been facing in our economy was inflation; inflation partly indigenous and partly imported, I think, to a large extent imported. The real difficulty we faced was the oil situation; we imported inflation and were exporting to the other countries at recessionary prices. We suffered both ways. That is why our prices were running out of our control. The measures which have been taken, you will see today, have not only enabled us to manage that situation but have also helped in bringing down the prices. Prices have stabilised and that is why it has now become possible to think in terms of finalising the plan also. Because once you are in a position to finalise the plan, then only more dependable growth will become possible.

The prices of essential commodities have fallen throughout the country. In the first month of emergency there was a minus rate of inflation of 1.9 per cent. Between July and December 1975, the wholesale prices have fallen by 5.4 per cent; even though the normal seasonal rise in the price was largely suppressed this year, the consumer prices for agricultural labourers showed a remarkable decline of 8.3 per cent between July and December 1975. Stabilisation of prices, industrial discipline and the attack on anti-social elements had given us a new hope and faith and a new vision and that is why our industrial production is picking up; in terms of coal production it has gone up by 12 per cent; in terms of alumina by 44 per cent; in terms of power generation, by 12 per cent or in terms of vanaspati, by 52 per cent. Production is picking up and for this I again wish to express my thanks to the co-operation of the

working class, and to the trade unions who have done a great deal. I am not now talking about the progress achieved by the railways, by the public sector and other industrial sectors because I know that my friend Mr. Unnikrishnan is getting very impatient; I promise him that I shall give him an opportunity.

The twenty-point programme has laid a great deal of emphasis on handloom. Handloom development has given us new hope and it is picking up. I should only like to say that so far as handloom is concerned we were able to clear accumulated stocks of handlooms Loans totalling Rs 4 72 crores have been given to the concerned States, and to All India Fabric Co-operative Marketing Society and alongwith that there was a subsidy of ten per cent from the Centre. It is also a fact that the development plan for handloom industry has been prepared and it provided for larger coverage of co-operatives and supplies. Standard cloth situation is very much better That is why we are now in a position to say that nobody is suffering from shortage. For socialisation of the urban land, the Bill is already before you I should like to say a word and finish The Government is keenly aware of the need for further intensifying the efforts for effective implementation of the programmes and in view of this it is proposed to suggest to my friend Mr. Bibhuti Mishra to withdraw his resolution because it is being adequately supervised at the state level and at the central level and the Prime Minister's Secretariat is co-ordinating the whole thing.

**श्री विभूति मिश्र** (मोतिहारा) : सभापति जी, 523 आदमियों में मुश्किल से रिजोल्यूशन वैनट में आता है, और जब आप कहते है कि जवाब न दे तो लोग समझेंगे कि रिजोल्यूशन का जवाब न देना उचित नही है । मैं ज्यादा नहीं बोलूगा चूकि हमारे साथी को रिजोल्यूशन मूव करना है ।

सदन के सभी सदस्यो ने मेरे प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन किया इस के लिए मैं उन का आभारी हूं । मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, अगर कुछ समय रहता तो और ज्यादा जवाब देते जिस से देश को पता चले कि हमारी सरकार क्या कर रही है । हमारे विरोध के तीन भाइयों को शक हुआ है, जैसे हमारे जिले में जब गांधीजी गये थे तो बडे बडे नेताओं को शक था कि प्लान्टर्स नहीं भागेंगे । लेकिन गांधी जी ने बड़े बडे नेताओं को कहा कि प्लान्टर्स भाग जायेंगे । सन् 1930 में मैं डा० राजेन्द्र बाबू के साथ घूमता था और मैं अपने जिले का डिक्टेटर था । उस वक्त उन्होंने कहा था। कि आज मालूम होता है कि गांधी जी की बात सही निकली । वैसे ही 1947 की 15 अगस्त तक लोगों को विश्वास नही था कि अंग्रेज यहां से चला जाएगा । हमारे बहुत से विरोधी भाइयों की और यहा तक कि हमारे पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग उस समय थे, जिन को यह विश्वास नही होता था कि अंग्रेज यहा से चला जाएगा ।

यह सत्य बात है कि हम यहा पर कुछ प्रस्ताव लाते है तो उन मे कुछ पर अमल करते हैं और कुछ पर अमल नही होता है लेकिन हम आगे बढ़ते जाते है । इसी तरह से यह जो 20 सूत्रा कार्यक्रम है, इन मे बॉंडेड लेबर को खत्म कर दिया गया है और सब से इम्पॉर्टेन्ट चाज यह है कि शहरी जमीन के बारे मे जो हम बीसियों बार चिल्लाया करते थे, उस की सीलिंग होनी चाहिए , आज हम देखते है कि सरकार वह बिल ले आई है और उस बिल को भी हम पास करेंगे ।

दूसरी बात यह है कि मावलंकर जी ने कहा कि कुछ लीगल और एडमिनिस्ट्रे-

[श्री विभूति मिश्र]

डिव हैंडिलंग हैं। यह ठीक है लेकिन मैं आप को बताता हू कि बिहार मे हाई कोर्ट मे बहुत से मुकदमे पड़े हुए हैं और हाई कोर्ट उनमे फैसला नही कर रहा है। सीलिंग के मामले पड़े हुए है। तो लीगल हैंडिल्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडिल्स भी है जैसा कि आप ने कहा कि नीचे के स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन नही होता है। ये दोनों दिक्कते हैं। (व्यवधान) इसलिए मैं कहता हू कि मावलंकर जी ने ठीक से समझा नही है मेरे प्रस्ताव को समझेंगे तो प्रस्ताव नही मालूम होगा।

दूसरी तरफ हमारे मेहता जी और सैकीरा जी को विश्वास नही है कि यह प्रोग्राम सफलीभूत होगा। मैं उन को बतलाना चाहता हू कि वे अपने जीवन काल मे ही देख लेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम सफलीभूत हो गया है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) मैंने यह कहा था कि आप काम नही करेंगे तो यह नही होगा।

श्री विभूति मिश्र मैं यह बताना चाहता हू कि गुजराल साहब ने मेरे एक सवाल का जवाब नही दिया। मेरे एक सवाल के जवाब मे गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया था। मेरा सवाल था

whether since Independence industries have been set up only in selected regions,

तो इस से जो लिस्ट दी है उसमे जिस एरिया से मैं आता हू वहा कोई इंडस्ट्री नही है।

सभापति महोदय मैं आप से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हू कि डिटेल्स मे मत जाएं। यह तो हम आपस मे बात कर के कर सकते है। आप थोड़ा सा सहयोग दीजिए।

श्री विभूति मिश्र आप सोशलिस्ट है तो मैं भी सोशलिस्ट हू। आप जरा सुनिये और घबराइये नही। मैं अभी समाप्त कर रहा हू। मैं यह कह रहा था कि इंडस्ट्री के मामले मे सरकार को हर एरिया के लिए ख्याल रखना चाहिए और पिछड़े हुए एरियाज का ज्यादा ख्याल रखिये।

गुजराल साहब ने एक बात कही कि पहला रिकार्ड ठीक नही था। हमारे पंडित द्वारिका नाथ तिवारी भी बैठ हुए है और वह इस बात को जानते हैं कि अंग्रेजो के जमाने में बनिया राज्य कोर्ट आफ वार्ड्स के कब्जे मे था और आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिए कि जमींदारी का रिकार्ड वहा का कितना अच्छा था और अब जब कि जमींदारी आप के हाथ मे आ गई है आप अपना रिकार्ड देख लीजिए। पता नही लगता है कि कोई रिकार्ड है या नही। अंग्रेजो के जमाने मे जो जमींदारी प्रथा था उस का रिकार्ड एक नम्बर का था।

तीसरी बात क्रेडिट की है। वह बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है आप किसानो के लिए फर्टिलाइजर्स और बिजली का भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं अन्त मे यही कहूंगा कि सरकार को इस 20 सूत्री कार्यक्रम को मनसा वाचा कर्मणा जल्दी से से जल्दी कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए और लोगो को इस के पूरा होने मे संदेह नही करना चाहिए।

18 hrs.

MR. CHAIRMAN I shall first put the amendments moved by Shri Sequeira and Shri Daga

*Amendments Nos. 1 to 3 were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: Does he want to withdraw his resolution?

SHRI BIBHUTI MISHRA: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw his resolution?

HON. MEMBERS: Yes.

*The Resolution was, by leave, withdrawn.*

---

**18.01 hrs.**

## RESOLUTION RE. CHANGES IN THE CONSTITUTION

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Sir, I beg to move:

"This House taking into consideration the experience of the working of the Constitution of India during the last twenty-five years and confronted with the tasks and challenges of social reconstruction is of the opinion that significant changes are called for in the constitutional framework of the country. The House, therefore, urges the Government of India to initiate constitutional amendments particularly in the nature of property rights and to secure meaningful realisation of the principles enshrined in the Preamble and the Directive Principles of the State Policy of the Constitution keeping intact the supremacy of Parliament, the federal structure and legitimate rights of the minorities, the Tribals, Harijans and other submerged sections of our population."

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): I am happy you have extended the time to accommodate the hon. member to move his resolution, but it is necessary to seek the pleasure of the House for extending the sitting beyond 6.

MR. CHAIRMAN: The private members' business started at 3.35 and 2-1/2 hours will be over only at 6.05.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): The year 1975 is the watershed year in the history of India. It was Justice Holmes who said that the life of the law has not been logic; it has been experience....

MR CHAIRMAN: You can continue on the next day.

**18.05 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 2, 1976/Magha 13, 1897 (Saka).*

GMGIPND—Job I—L.S. 2308—J.C, 3641—3-3-76—978